केंद्र और राज्य शासन से विज्ञापन के लिए अनुमोदित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

17 वर्षों से निरंतर....

Website:- www.malwaherald.com

RNI No. MPHIN/2010/33238
dainikmalwaherald@yahoo.com
malwaherald@gmail.com

मालवा हेराल्ड

महाकालेश्वर जी का संध्या काल आरती श्रृंगार दर्शन

सुविचार

मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाये...

वर्ष : 17 अंक : 29 | उज्जैन, गुरुवार 09 जुलाई 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य-1 रुपए

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में अधोसंरचनात्मक विकास और पुनर्वास कार्यों के लिये दी 2,300 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को 2031 तक निरंतर रखे जाने के लिए 495 करोड़ रूपये की मंजूरी

भोपाल/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में अनेक निर्णय लिए गए है। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास और पुनर्वास कार्यों को 2300 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव अनुसार राज्य डाटा सेंटर के आधुनिकीकरण, आई.टी एवं डिजास्टर रिकवरी सहित अन्य कार्यों के लिए मंत्रि-परिषद ने 800 करोड़ की मंजूरी दी है। विभाग के ही तीन अन्य प्रस्तावों पर विज्ञान पार्क-एकल नागरिक डाटाबेस परियोजना और बॉयो टेक्नालॉजी पार्क की स्थापना एवं संचालन के लिए वर्ष 2031 तक निरंतरता के लिए 123 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक और प्रस्ताव अनुसार ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत स्वामित्व योजना के निष्पादित हस्तांतरण अभिलेखों पर अतिरिक्त स्टांप शुल्क से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक ~2026 को भी मंत्रि-परिषद ने मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव अनुसार मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को वर्ष 2031 तक निरंतर रखे जाने के लिए 495 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इसी तरह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश उपार्जित गेहूँ, चना, ज्वार एवं बाजरा निस्तारण नीति ~ 2026 को भी मंत्रि-परिषद ने स्वीकृति दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव अनुसार मध्यप्रदेश के 65 नगरीय निकायों और उनके आस-पास के वन क्षेत्रों में नगरीय वन विकसित करने के लिए नमो हरित नगर योजना को 100 करोड़ की स्वीकृति दी है।

जल संसाधन विभाग द्वारा पृथक-पृथक 3 सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास और पुन~ विस्थापन के लिए 3 प्रस्ताव अनुसार मंत्रि-परिषद ने पन्ना जिले की केन-बेतवा लिंक परियोजना, रूंज सिंचाई परियोजना और मझगांव सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए अतिरिक्त रूप से 202 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि स्वीकृति दी है। मंत्रि-परिषद ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राजपत्रित सेवा भर्ती नियम ~ 2022 के तहत भर्ती प्रक्रिया को स्वीकृति दी। इसी तरह मंत्रि-परिषद द्वारा लीगल और डिफेंस काउंसिल सिस्टम योजना की वर्ष 2031 तक निरंतरता के लिए 42 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वित्त विभाग के प्रस्ताव अनुसार विभिन्न लिखतों पर देय उपकार में छूट देने का निर्णय लिया गया है। मंत्रि-परिषद ने शिक्षा विभाग की लोक-वित्त पोषित कार्यक्रमों योजनाओं एवं परियोजनाओं के परिक्षण की योजना को 1 अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक की निरंतरता के लिए 543 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है।

मंत्रि-परिषद ने एमपीएसईडीसी द्वारा संचालित एवं संग्रहीत म.प्र. स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार और अद्यतन डाटा सेंटर 3.0 परियोजना के लिए 800 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार म.प्र. स्टेट डाटा का आधुनिकीकरण, आईटी एवं डिजास्टर रिकवरी क्षमता विस्तार तथा संबंधित नॉन-आईटी अवसंरचना विकास किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना अंतर्गत सरकार की सेवाओं को संगठित करने व दक्ष इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रदान करने के लिए भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से भोपाल में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर 12 दिसंबर 2012 से सफलतापूर्वक संचालित है।

न्यूज ब्रीफ

आधुनिक खेती, तकनीक और बाजार... 20 लाख किसानों को रोजगार से जोड़ रही सरकार, गांवों में प्रगति मिशन हुआ शुरू

नई दिल्ली/ जीएनएस। गांवों में खेती को रोजगार और उद्यम से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने प्रगति मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत 20 हजार ग्रामीण युवाओं को कृषि-उद्यमी बनाया जाएगा, जो करीब 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीक, बाजार और वित्तीय सेवाओं से जोड़ेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रगति मिशन को शुरू किया। पहले चरण में यह परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल एवं असम में लागू होगी। लक्ष्य है गांवों में ऐसा मजबूत नेटवर्क तैयार करना, जिससे किसानों को खेती से जुड़ी अधिकांश सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकें और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हों। प्रशिक्षित कृषि-उद्यमी किसानों को मिट्टी की जांच, आधुनिक कृषि मशीनों और ड्रोन के उपयोग, खेती संबंधी सलाह, बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और बेहतर बाजार तक पहुंच दिलाने में मदद करेंगे। इससे खेती की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को पुनर्योजी (रेजेनरेटिव) खेती अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। यह देश में निजी क्षेत्र की भागीदारी वाला सबसे बड़ा कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित कृषि और समृद्ध गांवों के बिना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि केवल पारंपरिक खेती से किसानों की आय नहीं बढ़ेगी। इसके लिए फसल विविधीकरण, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना होगा।

तुरंत भंग किया जाए ट्रस्ट... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अशोक गहलोत बोले - जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए

नई दिल्ली/ जीएनएस। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में भले ही मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को आरोपों में घिरे ट्रस्ट के पदाधिकारियों के इस्तीफे स्वीकार करके और उनकी जगह नए लोगों की नियुक्ति करके इस मामले को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विवाद को और हवा दी है। उन्होंने कहा कि मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी से लोगों की आस्था पर जिस तरह से चोट पहुंची है, उनमें मंदिर ट्रस्ट को तुरंत भंग करना चाहिए। साथ ही चढ़ावा चोरी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में कराई जानी चाहिए।

कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह अविश्वास पैदा हुआ है, उससे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने खुद कहा कि यह चोरी नहीं बल्कि डकैती है। भाजपा और आरएसएस भी मान रहे कि गड़बड़ी हुई है तो फिर बचा क्या है। इसलिए इस ट्रस्ट को तुरंत भंग किया जाए। उन्होंने मामले की जांच कर रही एसआइटी पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित की गई एसआइटी पर लोगों को भरोसा नहीं है। वह बड़े लोगों को बचा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे की पूरी जानकारी सार्वजनिक की थी, उसी तरह मंदिर के दानदाताओं की सूची भी सार्वजनिक की जाए। वैसे भी मंदिर के निर्माण में सभी राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने दान दिया है। मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री रहते मदद की। गहलोत ने कहा कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब चंपत राय राजस्थान के भरतपुर से गैर कानूनी खदानों से पत्थर लेकर जा रहे थे।

कुछ-कुछ होता है से बहुत कुछ होता है तक, पीएम मोदी ने इंडोनेशिया से दुनिया को दिखाई भारत की ताकत

नई दिल्ली/ जीएनएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित किया और इस मंच से दुनिया को भारत की ताकत बताई।

पीएम मोदी ने भारत और इंडोनेशिया के मजबूत होते रिश्तों की भी बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं, तब कुछ-कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंगलवार, 7 जुलाई को इंडोनेशिया की संसद में संबोधन देते हुए कहा, मैं जहां-जहां गया, जिस किसी से मिला, हर चेहरे पर भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और आत्मीयता साफ दिखाई दे रही थी।

पीएम ने आगे भारत-इंडोनेशिया के रिश्तों को लेकर कहा, वैसे मैंने देखा कि यहां भारत का गाना कुछ-कुछ होता है, बहुत ही लोकप्रिय है। इस पर मैंने इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो से कहा, जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं, तब कुछ-कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है।

स्कूली शिक्षा में देश में चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ, उत्तर प्रदेश और बिहार अभी भी आकांक्षी श्रेणी में

नई दिल्ली/ जीएनएस। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में भले ही चंडीगढ़ ने देशभर में फिर से शीर्ष में जगह बनाई है, लेकिन अभी भी वह उत्कर्ष श्रेणी से काफी पीछे है। राष्ट्रीय सूचकांक में 1000 में से 761- 820 अंक यानी 61-70 प्रतिशत स्कोर प्राप्त करते हुए चंडीगढ़ ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआइ) 2.0 में उत्तम -3 ग्रेड हासिल किया है।

हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्कूली शिक्षा की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। ये सभी आंकाक्षी-1 श्रेणी में ही बने हुए हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यों की स्कूली शिक्षा की हालत पर 2025-26 की पीजीआई 2.0 रिपोर्ट जारी की है। इसमें दो श्रेणियों में छह क्षेत्रों में राज्यों की स्कूली शिक्षा की स्थिति को परखा गया था। इसका उद्देश्य राज्यों में स्कूली शिक्षा की कमियों को पहचानना और उनकी कमियों में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाना शामिल है। इसके तहत जो नतीजे सामने आए हैं, उनमें शीर्ष की तीन श्रेणियों यानी उत्कर्ष, उत्तम-1 और उत्तम-2 श्रेणी में कोई भी राज्य जगह नहीं बना पाया है। जबकि उत्तम-3 श्रेणी में सिर्फ चंडीगढ़ ने जगह बनाई है। दस श्रेणियों में जांचे जाने वाले इस प्रदर्शन में चंडीगढ़ को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्य प्रचेष्ठा-1, प्रचेष्ठा-2, प्रचेष्ठा-3 और आकांक्षी-1 की श्रेणी में हैं।

केरलम के वायनाड में भूस्खलन से पांच की मौत, राज्य के दो मंत्रियों ने कहा- इंसानों की वजह से हुई आपदा

वायनाड/ जीएनएस। केरलम के वायनाड जिले में मंगलवार को भूस्खलन से पांच लोगों की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गए। तीन लोग लापता हैं। यह दुर्घटना भारी बारिश के बीच कल्लाडी में मेप्पाडी-कल्लाडी टनल रोड प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल पर उस समय हुआ जब खुदाई के बाद जमा मलबा लगातार हो रही मूसलधार बारिश के कारण ढह गया।

बचावदल भारी मशीनों और खोजी कुत्तों के साथ बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान में जुटे हैं। अधिकारियों ने कहा कि निर्माण स्थल पर ढहे मिट्टी के टीले के नीचे दबे लापता श्रमिकों का पता लगाने की उम्मीद में बचाव प्रयास चल रहा है। मेप्पडी पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि मेप्पाडी में पिछले 24 घंटों में 226 मिमी बारिश दर्ज की गई है। यह भूस्खलन कल्लाडी में मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ, जहां कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली सुरंग सड़क परियोजना पर काम चल रहा था। भूस्खलन के समय वहां कई गाड़ियां और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को लाने-ले जाने वाली एक बस खड़ी थी। भूस्खलन में एक चर्च और पास के एक घर भी ढह गया।

गनीमत की बात यह रही कि घर पर ताला लगा था क्योंकि घर के लोग मक्का की हजयात्रा पर गए थे। चर्च के अंदर भी कोई नहीं था।

सीएम ने दो मंत्रियों को वायनाड भेजा- मुख्यमंत्री वीडी. सतीशन ने केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा कर लापता लोगों का पता लगाने और घायलों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री एपी. अनिल कुमार और कृषि मंत्री टी. सिद्दीक - को वायनाड भेजा है।

सतीशन ने कहा कि भूस्खलन की वजह मौसम का सही अलर्ट न मिलना नहीं था, बल्कि अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद समय पर मिट्टी का ढेर न हटाना इसकी वजह थी।

नशा मुक्त भारत का महासंकल्प, अब एआई से थमेगी ड्रग तस्करों की चाल

नई दिल्ली/ जीएनएस। भारत ने नशाखोरी और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे निर्णायक और अभूतपूर्व जंग का एलान कर दिया है। देश की युवा पीढ़ी को इस दलदल से बचाने और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में अपनी तरह का पहला नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 जारी किया गया है।

अगले तीन वर्षों में देश को पूरी तरह नशा मुक्त भारत बनाने का यह एक ऐसा भावपूर्ण और कठोर संकल्प है, जो देश के हर नागरिक को एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद देता है। इस 96 पन्नों के ऐतिहासिक रोडमैप को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को सौंपी गई है, जिसके साथ सरकार के 39 मंत्रालय और राज्यों की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स मिलकर काम करेंगी।

इसके तहत, अब एयरपोर्ट पर एआई-आधारित पैसेंजर प्रोफाइलिंग सिस्टम लगाया जाएगा।

केंद्रीय सूचना आयोग ने MCD को दिए निर्देश, आवासीय लिफ्ट योजनाओं-मानचित्रों और रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की सलाह

नई दिल्ली/ जीएनएस। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को सलाह दी है कि वह आवासीय लिफ्ट स्थापना योजनाओं, भवन मानचित्रों, अनुमतियों और संबंधित रिकार्ड को सार्वजनिक डोमेन में सक्रिय रूप से उपलब्ध कराए, यह देखते हुए कि ऐसी जानकारी बार-बार सार्वजनिक प्रासंगिकता की है।

सूचना आयुक्त विनोद कुमार तिवारी ने आरटीआइ अधिनियम की धारा 25 के तहत जारी की गई सलाह में कहा कि इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और व्यक्तिगत आरटीआइ आवेदनों की आवश्यकता कम होगी।

सीआईसी ने एमसीडी को दी सलाह- यह सलाह एक एमसीडी सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआइओ) के खिलाफ लिफ्ट स्थापना से संबंधित रिकार्ड पर जानकारी प्रदान करने में देरी के मामले में कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही के निपटारे के दौरान दी गई।

आयोग ने बताया किया कि इस मामले में मांगी गई जानकारी आवासीय परिसरों में लिफ्टों की स्थापना से संबंधित अनुमतियों, स्वीकृतियों, योजनाओं और संबद्ध दस्तावेजों से संबंधित थी।

आयोग ने कहा कि स्वीकृत भवन योजनाएं पहले से ही नागरिक निकाय द्वारा सक्रिय रूप से प्रकट की जा रही हैं, अब, यह भी समझदारी है कि भवनों में लिफ्टों की स्थापना से संबंधित जानकारी को सक्रिय रूप से प्रकट किया जाए, जिसमें रेट्रोफिटिंग/रेट्रो-स्थापना से प्रदान की गई लिफ्टें भी शामिल हैं। आयोग ने एमसीडी को सलाह दी कि वह लिफ्टों की स्थापना के लिए अनुमतियों या स्वीकृतियों के अनुदान, लागू दिशा-निर्देशों, प्रक्रियाओं, प्रारूपों और संबंधित रिकार्ड को सार्वजनिक डोमेन में सक्रिय रूप से उपलब्ध कराएं, ताकि आरटीआइ अधिनियम की धारा 4(1)(बी) की भावना के अनुरूप पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके।

12.5% टैरिफ लगाने के प्रस्ताव पर भारत की दो टूक, US से मांगे सबूत

नई दिल्ली/ जीएनएस। भारत ने अमेरिका से उस प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है, जिसके तहत जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर रोक लगाने में कथित विफलता के चलते भारत पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही गई है।

इतना ही नहीं भारत ने किसी भी खास चिंता को दूर करने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के साथ बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है।

क्या है पूरा विवाद- यूएसटीआर ने 11 और 12 मार्च, 2026 को जबरन श्रम और जरूरत से ज्यादा औद्योगिक क्षमता से जुड़ी चिंताओं को लेकर 60 देशों के खिलाफ दो अलग-अलग सेक्शन 301 जांच शुरू की थीं। तीन जून को यूएसटीआर ने जबरन श्रम से जुड़ी जांच के नतीजे जारी किए और 54 देशों से होने वाले आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मैक्सिको और पाकिस्तान से होने वाले आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ और भारत व चीन सहित 48 अन्य अर्थव्यवस्थाओं से होने वाले आयात पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात शामिल है। यह उपाय अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है और इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

छह जुलाई को यूएसटीआर को सौंपे गए अपने जवाब में भारत ने कहा कि यूएसटीआर उन सुबूतों को पेश करने में नाकाम रहा है, जिनसे यह साबित हो सके कि इन देशों में प्रतिबंध न होने से बाजार की स्थितियों में निर्णायक या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होती है और नियमों का पालन करने वाली कंपनियों के मुनाफे पर बुरा असर पड़ता है।

सेक्शन 301 के गलत इस्तेमाल पर भारत की आपत्ति- भारत ने आगे कहा, सिर्फ जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर रोक नहीं होने को सेक्शन 301 के तहत गलत नहीं माना जा सकता है। भारत ने कहा कि यूएसटीआर ने जिन 60 देशों में चल रहे कानून और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को विशेष विश्लेषण नहीं किया है। इसके बजाय उसने बिना यह देखे कि देश कौन से खास उपाय लागू कर रहे हैं, एक व्यापक फैसला सुना दिया।

रेवती रेंज में गूंजे सटीक निशाने, 750 शूटरों के साथ प्री-स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का भव्य समापन

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश स्टेट रायफल एसोसिएशन के तत्वावधान में रेवती रेंज में आयोजित 29वीं .22 बोर रायफल एवं पिस्टल स्टेट चैंपियनशिप तथा .177 बोर रायफल एवं पिस्टल की तीसरी प्री-स्टेट चैंपियनशिप का मंगलवार को भव्य समापन हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लगभग 750 निशानेबाजों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कई दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए अपनी तैयारियों का दमखम दिखाया।

समापन समारोह में विभिन्न वर्गों के विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, वहीं परिजनों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर इंडिया शूटिंग टीम के कोच एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक दुबे, नेशनल रायफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के अधिकारी डी.के. शुक्ला, मध्यप्रदेश स्टेट रायफल एसोसिएशन के सचिव राकेश गुप्ता, एसोसिएशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रियांशी गुप्ता तथा पुष्पेंद्र सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। इनके साथ विभिन्न शूटिंग टीमों के कोच, बीएसएफ के अधिकारी, बड़ी संख्या में शूटर एवं उनके अभिभावक भी समारोह में शामिल हुए।

अतिथियों ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों में सफलता का आधार अनुशासन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में शूटिंग खेल लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए अन्य प्रतिभागियों को भी निरंतर मेहनत कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश दिया।

आयोजन के सफल संचालन पर मध्यप्रदेश स्टेट रायफल एसोसिएशन के पदाधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों, निर्णायकों एवं आयोजन समिति की सराहना की गई। प्रतियोगिता के सफल समापन के साथ ही खिलाड़ियों ने आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए अपनी तैयारियां और तेज करने का संकल्प लिया। यह आयोजन प्रदेश में शूटिंग खेल को नई दिशा देने और युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

589.63 हैक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। धार वन मंडल ने वन भूमि संरक्षण एवं अतिक्रमण नियंत्रण अभियान के तहत जनवरी से मई 2026 के बीच कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 589.63 हैक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। यह कार्रवाई वन विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन, पुलिस, ग्राम वन समितियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 7 वन परिक्षेत्रों में का गई।

विभागीय कार्रवाई में वन परिक्षेत्र धार में 100.55 हैक्टेयर, धामनोद में 35.10हैक्टेयर, मांडव में 50.78 हैक्टेयर, सरदारपुर में 50.62 हैक्टेयर, टांडा में 93.76 हैक्टेयर, बाग में 202.82 हैक्टेयर तथा कुक्षी में 56.00 हैक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। धार वन मंडल में कुल 589.63 हैक्टेयर वन भूमि पुनः वन विभाग के संरक्षण में लाई गई। अभियान का उद्देश्य वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर उसका पुनर्वनीकरण करते हुए प्राकृतिक वन संपदा का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर सागौन रूट-शूट की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अधिकारियों एवं मैदानी कर्मचारियों को वैज्ञानिक पद्धति से सागौन रूट-शूट रोपण, पौध संरक्षण एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। वन भूमि सार्वजनिक एवं प्राकृतिक संपदा है, जिसका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वन मंडल अधिकारी श्री विजयानंथम टी.आर. ने चेतावनी दी है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कलेक्टरग ने निर्माणाधीन मुसाखेड़ी, आईटी पार्क, देवास नाका ओव्हरब्रिज का किया निरीक्षण

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने आज रिंग रोड स्थित मुसाखेडी चौराहा, आईटी पार्क और देवास नाका ओव्हरब्रिज का निर्माणाधीन स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर श्री वर्मा के साथ नगर निगमायुक्त श्री क्षितिज सिंघल, अनुविभागीय अधिकारी श्री घनश्याम धनगर, एमपीआरडीसी ब्रिज सेल के प्रबन्धक एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री वर्मा ने तीनों निर्माणाधीन ब्रिज के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से प्राप्त की। कलेक्टर श्री वर्मा ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को ब्रिज निर्माण कार्य में और अधिक गति लाने तथा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीनों ओव्हरब्रिज क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ-साथ आम नागरिकों को आवागमन में बड़ी राहत प्रदान करेगें। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि बारिश की वजह से निर्माण स्थल के आसपास जल भराव और यातायात जाम की स्थिति निर्मित नहीं हो। साथ ही पैदल चलने वालों के लिए सुविधाजनक पैसेज बनाये जाए, आवश्यकता होने पर पेंचवर्क करें। उन्होंने ब्रिज निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को कहा कि यदि पैदल चलने वाले नागरिकों के लिए पैसेज समय सीमा में नहीं बना तो पेनाल्टी लगाई जायेगी।

रुद्र मीडिया हाउस में गूंजा सफलता का विजय मंत्र, इंडिया शूटिंग टीम के कोच दीपक दुबे और सीईओ प्रियांशी गुप्ता ने साझा किए प्रेरक अनुभव'

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान इंडिया शूटिंग टीम के कोच दीपक दुबे एवं मध्यप्रदेश स्टेट रायफल एसोसिएशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रियांशी गुप्ता ने रुद्र मीडिया हाउस पहुँचकर मीडिया हाउस के संचालक हर्ष कुशवाहा से विशेष मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों अतिथियों ने अपने खेल जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

विशेष बातचीत के दौरान इंडिया शूटिंग टीम के कोच दीपक दुबे ने अपने लंबे खेल एवं कोचिंग अनुभव को साझा करते हुए बताया कि किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे अनुशासन, निरंतर अभ्यास, धैर्य और सकारात्मक सोच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि शूटिंग ऐसा खेल है जिसमें मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि यदि वे इस खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो उन्हें नियमित अभ्यास के साथ अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिभा तभी निखरती है जब खिलाड़ी कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे।

वहीं मध्यप्रदेश स्टेट रायफल एसोसिएशन की सीईओ प्रियांशी गुप्ता ने अपने शूटिंग करियर की प्रेरणादायक यात्रा साझा करते हुए बताया कि उन्होंने भी चुनौतियों का सामना करते हुए इस मुकाम तक का सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में शूटिंग खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एसोसिएशन लगातार कार्य कर रही है। राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

प्रियांशी गुप्ता ने बताया कि एसोसिएशन का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण एवं छोटे शहरों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी मंच उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश एवं देश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि आगामी समय में खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर, प्रतियोगिताएं एवं विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

रुद्र मीडिया हाउस के संचालक हर्ष कुशवाहा ने दोनों अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल जगत की प्रेरणादायक कहानियों को समाज तक पहुंचाना मीडिया की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवाद युवाओं को अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देते हैं तथा खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हैं।

इस अवसर पर हुई चर्चा में खेलों के विकास, युवाओं की भागीदारी, आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था तथा शूटिंग के बढ़ते भविष्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और दोनों अतिथियों ने रुद्र मीडिया हाउस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों को समाज के सामने लाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इंदौर जू में मिलेगा 'डिजिटल जंगल' का रोमांच, 14D थिएटर में बारिश, जंगल और वाइल्ड लाइफ का होगा जीवंत अनुभव

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (जू) में जल्द ही शहरवासियों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से जंगल और वन्यजीवन का अनूठा एवं रोमांचकारी अनुभव मिलने वाला है। इंदौर नगर निगम द्वारा जू परिसर में अत्याधुनिक 14D थिएटर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। निर्माण पूरा होते ही इस अत्याधुनिक सुविधा का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया जाएगा।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बुधवार को निर्माणाधीन 14D थिएटर का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वच्छता प्रभारी अश्विनी शुक्ला, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया सहित नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। महापौर ने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित एजेंसी की सराहना की और समयबद्ध तरीके से शेष कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा था कि जब दूसरे शहर सोचते हैं, तब तक इंदौर वह काम कर चुका होता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम लगातार नवाचार कर रहा है। इंदौर जू में बनने वाला 14D थिएटर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के चुनिंदा आधुनिक आकर्षणों में शामिल होगा।

उन्होंने बताया कि 14D थिएटर में दर्शकों को केवल फिल्म देखने का अनुभव नहीं मिलेगा, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक की मदद से बारिश की फुहार, तेज हवा, पानी की छींटें, जंगल का वातावरण, वन्यजीवों की गतिविधियां और रोलर कोस्टर जैसे रोमांचक प्रभावों का वास्तविक अहसास कराया जाएगा। विशेष प्रभावों और आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से बच्चे और बड़े स्वयं को जंगल के बीच महसूस करेंगे तथा वन्यजीवों के जीवन और प्रकृति संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी रोचक अंदाज में प्राप्त कर सकेंगे।

महापौर ने बताया कि 14D थिएटर के साथ डिजिटल गार्डन, डिजिटल भूलभुलैया (डिजिटल मेज़) और डिजिटल एक्सपीरियंस जोन भी विकसित किए जा रहे हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से मनोरंजन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित की जा रही है और अब केवल अंतिम चरण के कुछ कार्य शेष हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में इसका लोकार्पण किया जाएगा।

महापौर ने विश्वास जताया कि इंदौर जू का यह डिजिटल अनुभव बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए यादगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वयं को जंगल की रोमांचक दुनिया का हिस्सा महसूस करेगा। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह डिजिटल जू न केवल शहरवासियों के लिए नया आकर्षण बनेगा, बल्कि इंदौर के पर्यटन को भी नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निर्माणाधीन सड़कों का आयुक्त ने किया निरीक्षण, जल निकासी और सुरक्षा व्यवस्था पर दिया विशेष जोर

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बुधवार को शहर में निर्माणाधीन विभिन्न सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों को कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता बनाए रखने तथा वर्षाकाल को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा और जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, अधीक्षण यंत्री पी.एस. कुशवाह, नरेश जायसवाल, पराग अग्रवाल, निर्माण एजेंसी के महेंद्र अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आयुक्त ने सदर बाजार से गुटकेश्वर महादेव मंदिर मार्ग, अन्नपूर्णा से रिंग रोड तथा मुसाखेड़ी सर्विस रोड पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान निर्माण स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े।

इसके बाद आयुक्त ने जमजम चौराहा से स्टार चौराहा तक निर्माणाधीन मास्टर प्लान सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क निर्माण के साथ-साथ जलभराव की समस्या से बचने के लिए स्टॉर्म वॉटर लाइन का कार्य भी समानांतर रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान ही प्रभावी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में बारिश के समय नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

आयुक्त क्षितिज सिंघल ने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता के साथ तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी विकास कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर पूर्ण किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से नियमित मॉनिटरिंग करने और निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए।

पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया होगी और तेज व पारदर्शी, इंदौर में संभाग स्तरीय पुलिस प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आमजन को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को पुलिस कमिश्नरेट इंदौर में पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए संभाग स्तरीय पुलिस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इंदौर संभाग के आठ जिलों के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पासपोर्ट सत्यापन से जुड़े तकनीकी और प्रक्रियागत विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शीतांशु चौरसिया, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) आर.के. सिंह, पुलिस उपायुक्त (आसूचना एवं सुरक्षा) अमन सिंह राठौड़, पुलिस मुख्यालय भोपाल की सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) रश्मि मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (आसूचना) प्रियंका डुडवे तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल की टीम से सुमित कुमार और रवि माने उपस्थित रहे।

सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित जीवन बना जनआंदोलन, इंदौर में सेफ क्लिक 2.0 अभियान का भव्य समापन

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक कर डिजिटल सुरक्षा को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाए गए सेफ क्लिक 2.0 अभियान का बुधवार को इंदौर के अभय प्रशाल में भव्य समापन हुआ। 24 जून से 8 जुलाई 2026 तक चले इस 15 दिवसीय अभियान के दौरान इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने शहरभर में व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर 80 लाख से अधिक लोगों तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाया।

समापन समारोह पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध) एवं अभियान की नोडल अधिकारी मीना चौहान, नगरीय इंदौर के सभी पुलिस उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी, विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, बड़ी संख्या में स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी तथा आमजन सहित लगभग तीन हजार लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध) मीना चौहान द्वारा अभियान की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी के साथ हुई। उन्होंने बताया कि बीते 15 दिनों में इंदौर पुलिस ने शहर के हर वर्ग तक पहुंचकर साइबर सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक नवाचार किए। उन्होंने अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी विभागों, संस्थाओं और नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

अपने संबोधन में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और उनसे बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम जागरूकता एवं सतर्कता है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, कॉलोनियों, बस्तियों, बैंकों, होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों, प्रमुख बाजारों, मॉल, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर व्याख्यान, नुक्कड़ नाटक, गीत-संगीत, नृत्य, रंगोली एवं पेंटिंग प्रतियोगिताएं, साइबर सुरक्षा रथ, साइकिल रैली, मैराथन, पोस्टर-बैनर, पंपलेट वितरण, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लोक परिवहन वाहनों एवं सिनेमाघरों में जागरूकता वीडियो, डिलीवरी पार्टनर्स के साथ विशेष अभियान तथा साइबर हैकेथॉन जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने और साइबर ठगी से बचने के व्यावहारिक उपाय बताए गए।

उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का सावधानीपूर्वक उपयोग करे और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में सतर्कता बरते, तो अधिकांश साइबर अपराधों से बचा जा सकता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इंदौर पुलिस भविष्य में भी साइबर सुरक्षा को लेकर ऐसे जनहितैषी अभियान लगातार चलाती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस आयुक्त ने उपस्थित सभी अतिथियों, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा की शपथ भी दिलाई।

अभियान के दौरान इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने कुल 307 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें 275 से अधिक ऑफलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से पांच लाख से अधिक नागरिकों को सीधे जागरूक किया गया, जबकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संचालित डिजिटल अभियान के माध्यम से 75 लाख से अधिक लोगों तक सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित जीवन का संदेश पहुंचाया गया।

पुजारियों को मिले किसान का अधिकार, फार्मर आईडी व कृषि ऋण की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के मंदिरों में सेवा दे रहे पुजारियों के हितों को लेकर बुधवार को वैष्णव बैरागी समाज के तत्वावधान में आर्यावर्त षड्दर्शन साधु मंडल एवं श्री रामानंदी नवनिर्माण सेना के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मंदिरों के पुजारियों को किसान के रूप में मान्यता दिलाने, फार्मर आईडी जारी करने, कृषि कार्य के लिए खाद-बीज उपलब्ध कराने तथा सहकारी बैंकों से कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करने की मांग की गई।

समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले के अधिकांश पुजारी धार्मिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ-साथ अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य भी करते हैं। इसके बावजूद भूमि संबंधी तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण वे किसान के रूप में पंजीकृत नहीं हो पा रहे हैं। परिणामस्वरूप उन्हें फार्मर आईडी नहीं मिल रही है और वे शासन द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं, अनुदान, खाद-बीज वितरण तथा सहकारी बैंकों से मिलने वाली ऋण सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

ज्ञापन में मांग की गई कि इंदौर जिला सहकारी बैंक की तर्ज पर नीमच जिले में भी मंदिरों के पुजारियों के लिए विशेष कृषि ऋण योजना प्रारंभ की जाए। साथ ही पात्र पुजारियों के लिए फार्मर आईडी जारी करने की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जाए, ताकि उन्हें शासन की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।

प्रतिनिधियों ने यह भी आग्रह किया कि जिले की सभी सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, जिससे पात्र पुजारियों को समय पर खाद, बीज, कृषि ऋण एवं अन्य कृषि संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उनका कहना था कि वर्तमान व्यवस्था में कई पुजारी केवल तकनीकी कारणों से सरकारी लाभ से वंचित हैं, जबकि वे वर्षों से कृषि कार्य करते आ रहे हैं।

समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शासन उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेता है तो इससे पुजारियों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, उनकी आजीविका अधिक मजबूत बनेगी तथा वे धार्मिक सेवाओं के साथ कृषि कार्य भी बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इससे मंदिरों की धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को भी मजबूती मिलेगी।

अंत में समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया, ताकि जिले के पात्र पुजारियों को भी अन्य किसानों की तरह शासन की कृषि कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन और पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल धनेरिया पहुंचे और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन बुधवार को धनेरिया पहुंचीं और पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल से उनके आवास पर मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा। इस दौरान मीनाक्षी नटराजन ने नंदकिशोर पटेल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिजनों एवं मित्रों से उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि एक-दूसरे का हालचाल जानना और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाना सामाजिक और मानवीय कर्तव्य है। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। सभी ने पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

कलेक्टर ने पिपलिया रुंडी में एनएलएम बकरी पालन इकाई का किया निरीक्षण

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को ग्राम पिपलिया रुंडी स्थित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) उद्यमिता विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित बकरी पालन इकाई का निरीक्षण किया। उन्होंने इकाई की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर परियोजना के क्रियान्वयन तथा पशुपालन गतिविधियों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान हितग्राही पशुपालक श्री गोपाल जाटव ने बताया कि उनके फार्म पर वर्तमान में लगभग 500 बकरियों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह परियोजना लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की गई है। इसके लिए 40 लाख रुपये का बैंक ऋण, 45 लाख रुपये का शासकीय अनुदान तथा 12 लाख रुपये का हितग्राही अंशदान स्वीकृत किया गया है। श्री जाटव ने बताया, कि इस परियोजना से उन्हें प्रतिमाह लगभग एक लाख रुपये की आय प्राप्त हो रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है तथा पशुपालन के क्षेत्र में स्वरोजगार के नए अवसर भी विकसित हुए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री चंद्रा ने परियोजना के संचालन,पशुओं के रखरखाव तथा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेते हुए शासन की स्वरोजगार एवं पशुपालन प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया।

मल्हारगढ़ क्षेत्र में फिर सक्रिय हुए बाइक चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, दो महीने में 9वीं बाइक, 1 भैंस व 3 पाड़िया चोरी

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मल्हारगढ़ क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा घटना में दिनदहाड़े एक बाइक चोरी होने से क्षेत्र में दहशत और नाराजगी का माहौल है। खास बात यह है कि पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना स्थल से डायल-112 वाहन महज 10 मीटर तथा मल्हारगढ़ थाना लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित होने के बावजूद चोर बेखौफ होकर बाइक लेकर फरार हो गए। पीड़ित संजय पिता रामचंद्र गुप्ता, निवासी स्टेशन रोड, मल्हारगढ़ ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनकी हीरो होंडा पैशन प्रो (काले रंग) क्रमांक एमपी 14 एमएच 4277 दोपहर करीब 2ः15 बजे घर के पास गली में खड़ी थी। शाम करीब 5 बजे जब वे बाहर आए तो बाइक मौके से गायब थी। आसपास काफी तलाश करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर उन्होंने मल्हारगढ़ थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि चोरी की पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। अब लोगों की नजर पुलिस की जांच पर टिकी है कि फुटेज के आधार पर आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पिछले करीब दो महीनों में मल्हारगढ़ क्षेत्र से 9 मोटरसाइकिलें, 1 भैंस और 3 पाड़िया चोरी हो चुकी हैं। लोगों का आरोप है कि अब तक चोरी गई एक भी मोटरसाइकिल बरामद नहीं हो सकी है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगरवासियों का यह भी कहना है कि कई मामलों में शिकायत तो दर्ज कर ली जाती है, लेकिन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार आवेदन पर प्राप्ति की सील तक नहीं लगाई जाती, जिससे शिकायतकर्ताओं में कार्रवाई को लेकर असमंजस बना रहता है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों और आम नागरिकों में भय का माहौल है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शीघ्र पहचान कर गिरफ्तारी की जाए, चोरी गए वाहनों एवं पशुओं की बरामदगी सुनिश्चित की जाए तथा नगर में रात्रि गश्त और निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, ताकि चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इधर प्रभारी अनिल रघुवंशी ने बताया कि मामले में शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। फुटेज के आधार पर संदिग्ध आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।

जिला कांग्रेस बैठक में संगठन मजबूती और जनआंदोलनों की रणनीति पर जोर, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने कहा- जनता के मुद्दों पर सड़क से सदन तक लड़ेगी कांग्रेस

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि कांग्रेस अब केवल विपक्ष की भूमिका तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जनता से जुड़े हर मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक निर्णायक संघर्ष करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को अनुशासन, एकजुटता और सक्रियता के साथ मजबूत बनाते हुए जनआंदोलनों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। गांधी भवन स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि नीट पेपर लीक, किसानों को खाद-बीज की समस्या, भ्रष्टाचार के आरोप तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर कांग्रेस जनता की आवाज बनकर संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि 14-15 जुलाई को प्रस्तावित साइकिल यात्रा तथा 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विरोध-प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटियों को बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने राज्यसभा चुनाव में उनका नामांकन पत्र निरस्त होने, संगठन की मजबूती तथा आगामी नगरीय निकाय एवं विधानसभा चुनावों की तैयारियों से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। बैठक में जिला प्रभारी एवं सुसनेर विधायक भेरूसिंह बापू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बृजेश सक्सेना एवं मनोहर अंब ने किया।

नीमच जिले में बड़ा सड़क हादसाः 40 बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन बीच रास्ते पलटी

चालक फरार; मौके पर जुटी भीड़, बाल-बाल बची सभी की जान

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले की मनासा तहसील में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बरखेड़ा-बरखेड़ी मार्ग पर स्कूली बच्चों से भरी एक वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। वैन में करीब 40 छात्र-छात्राएं सवार थे। राहत की बात यह रही कि सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई।

जानकारी के अनुसार, हादसे के समय वैन बनी गांव स्थित गैलेक्सी पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल की ओर जा रही थी। इसमें बरखेड़ा, बरखेड़ी और पावटी क्षेत्र के बच्चे सवार थे। अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ने से वैन पलट गई। दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए वैन में फंसे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।

घटना के बाद क्षेत्र में स्कूल प्रबंधन के प्रति लोगों में नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों के साथ-साथ वाहन की फिटनेस, चालक की लापरवाही तथा स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी की भी जांच की जा रही है।

शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा, ई-अटेंडेंस के नाम पर वेतन कटौती एवं दंडात्मक कार्रवाई आदेश निरस्त की मांग

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने ई-अटेंडेंस के आधार पर शिक्षकों का वेतन रोकने, वेतन कटौती करने तथा अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक एवं निलंबनात्मक कार्रवाई के प्रावधान वाले आदेश का कड़ा विरोध करते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। संघ के संभागीय अध्यक्ष शंकरलाल आंजना तथा मंदसौर के जिलाध्यक्ष विक्रम शर्मा, सचिव भरतलाल पोपंडिया एवं कोषाध्यक्ष कांतिलाल राठौर ने संयुक्त रूप से बताया कि मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा प्रदेश के लगभग तीन लाख शिक्षक-शिक्षिकाओं की ई-अटेंडेंस से संबंधित समस्याओं को लेकर स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है।

ज्ञापन में 01 जुलाई को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी उस आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है, जिसमें ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होने की स्थिति में वेतन कटौती तथा संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं निलंबन की कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर, प्रदेश महामंत्री राकेश गुप्ता एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष विनोद कुमार पुनी ने कहा कि विभाग स्वयं स्वीकार कर चुका है कि प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में ई-अटेंडेंस सफलतापूर्वक दर्ज हो रही है तथा अधिकांश जिलों में इसकी सफलता 94 से 95 प्रतिशत तक है। ऐसी स्थिति में नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल, बिजली अथवा ऐप संबंधी तकनीकी समस्याओं के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर शिक्षकों को दोषी ठहराकर वेतन कटौती करना न्यायसंगत नहीं है।

कलेक्टर ने मालखेड़ा एवं जावी के प्राथमिक विद्यालयों का किया निरीक्षण

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को जिले के मालखेड़ा एवं जावी स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता तथा विद्यालयीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मालखेड़ा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कलेक्टर श्री चंद्रा ने छात्र-छात्राओं के बैठने की व्यवस्था का अवलोकन किया।

कलेक्टर ने जावी में पूजा घाणी एवं लघु उद्योग का किया निरीक्षण

पीएमएफएमई योजना के तहत स्थापित इकाई का लिया जायजा

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्र ने बुधवार को ग्राम जावी स्थित पूजा घाणी एवं लघु उद्योग का निरीक्षण कर वहां संचालित मूंगफली तेल उत्पादन इकाई का अवलोकन किया। उन्होंने इकाई में मूंगफली से तेल निकालने, रिफाइनिंग की प्रक्रिया तथा उत्पादन व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

पीएमएफएमई (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना) से लाभान्वित हितग्राही श्री शंभूलाल राठौर ने कलेक्टर को बताया, कि शासन की इस योजना के अंतर्गत उन्हें 2.59 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ है, जिसके माध्यम से उन्होंने लघु उद्योग स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि तेल उत्पादन के साथ-साथ पशु आहार के लिए खल का भी उत्पादन होता है, जिससे उनकी मासिक आय लगभग 30 हजार रुपये तक हो जाती है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने योजना के माध्यम से स्वरोजगार एवं आयवृद्धि के संबंध में जानकारी लेते हुए इकाई के संचालन की सराहना की तथा शासन की रोजगारोन्मुखी योजनाओं का प्रभावी लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर बल दिया।

इस अवसर पर एसडीएम श्री पराग जैन, तहसीलदार श्री संतोष कुमार तथा उद्यानिकी विभाग से श्री पी.एस. कनेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कोर्ट तक पहुंच मार्ग की दयनीय हालत पर देना पड़ा धरना, जज साहब और वकीलों के अध्यक्ष के हस्तक्षेप पर अधिकारी हुए सक्रिय

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भगवान श्री पशुपतिनाथजी मंदिर एवं जिला न्यायालय परिसर जाने के रास्ते की दयनीय हालत एवं यहां पर हो रहे गड्ढों और बदबू तथा गंदगी से मुक्ति के लिए बुधवार को अभिभाषक डॉ. राघवेंद्र सिंह तोमर एवं साथी धरने पर बैठे गए। इससे सड़क पर जाम लग गया। जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष रघुवीर सिंह पंवार एवं वरिष्ठ अभिभाषक साथियों ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से की चर्चा की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा के हस्तक्षेप के बाद मौके पर नायब तहसीलदार पहुंचे। सड़क मरम्मत कार्य शुरू किया गया। इस दौरान आज शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक का समय दिया, अगर सड़क का काम प्रारंभ नहीं हुआ तो पुनः धरना होगा।

अंबेडकर चौराहे से भगवान श्री पशुपतिनाथजी मंदिर एवं जिला सत्र न्यायालय तथा शहर क्षेत्र में जाने के रास्ते पर हो रहे भारी गड्ढों तथा गंदगी व बदबू की समस्या से जूझ रहे अभिभाषको में पिछले कई दिनों से भारी रोष व्याप्त है। यहाँ एक युवा अभिभाषक दुर्घटना का शिकार हुआ और असमय निधन हो गया। इसी प्रकार आये दिन दुर्घटनाएं घट रही है। बुधवार दोपहर 3 बजे अभिभाषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. राघवेंद्र सिंह तोमर अपने अभिभाषक साथियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर चौराहा पर हो रहे गड्ढों के बीच जाकर सड़क पर बैठ गए तथा रोड जाम हो गया। धीरे-धीरे वहां पर बड़ी संख्या में आमजन व अभिभाषकगण उपस्थित हुए। लगभग 2 घंटे चले प्रदर्शन के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय अनीश मिश्रा एवं जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष रघुवीर सिंह पवार द्वारा हस्तक्षेप किया गया। अधिकारियों को फटकार लगाई गई, उसके बाद मौके पर नायब तहसीलदार अभिषेक चौरसिया पहुंचे और सड़क मरम्मत कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। थोड़ी देर बाद ही पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया तथा आश्वासन दिया गया कि जल्द गंदगी को हटाया जाएगा। इस आश्वासन के बाद अभिभाषक संघ अध्यक्ष रघुवीर सिंह पवार, वरिष्ठ अभिभाषक पुखराज दशोरा, मोहम्मद अजीज कुरैशी लिए, अशोक कटलाना, मोहनसिंह चौहान आदि ने मिलकर निर्णय किया और निर्णय के बाद अभिभाषक डॉ. राघवेंद्र सिंह तोमर ने अपना धरना समाप्त किया।धरने में शामिल होने वाले अभिभाषक विनोद शर्मा, दिलीप देवड़ा, कुलदीप पंवार, श्री नीमे आदि एवं महिला सामाजिक कार्यकर्ता अनिता भदौरिया, योगिता बैरागी, दशरथ सिंह राठौड़, घनश्याम लोहार सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने भागीदारी करी। अभिभाषक संघ की ओर से चेतावनी दी गई कि अगर गुरुवार दोपहर 2 बजे तक मरम्मत कार्य नहीं हुआ, तो पुनः धरना प्रदर्शन होगा।

चलती ट्रक से सामान उड़ाने वाला गिरोह सक्रिय, तिरपाल काटकर दो कट्टे चोरी, चालक ने पुलिस पर शिकायत नहीं लेने का लगाया आरोप

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पिपलिया-मल्हारगढ़-नीमच हाईवे पर चलती ट्रकों से माल चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय होने है। गिरोह के सदस्य सुनसान स्थानों पर चलती ट्रकों पर चढ़कर तिरपाल काटते हैं और माल नीचे उतारकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामले में ट्रक चालक एवं मालिक राजेश पिता प्यारेलाल कोहली ने आरोप लगाया है कि उनकी चलती ट्रक से 30-30 किलो वजन के दो कट्टे चोरी कर लिए गए। इतना ही नहीं, जब वे घटना की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे तो उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई।

जानकारी के अनुसार राजेश कोहली ने बताया कि प्रतिदिन पिपलिया से नीमच के बीच ट्रक क्रमांक एमपी-14 जीसी-1568 से माल परिवहन का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार करीब पौने छह बजे की है। उनकी ट्रक में करीब 200 कट्टे माल भरा हुआ था। ट्रक जैसे ही पिपलिया में हाईवे पर ब्रिज पर चढ़ा उसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने चलती ट्रक पर चढ़कर तिरपाल काट दिया। इसके बाद ट्रक में रखे 30-30 किलो वजन के दो कट्टे नीचे उतार लिए और मौके से फरार हो गए। राजेश कोहली ने बताया कि घटना के दौरान उनकी नजर पीछे चल रही एक मोटरसाइकिल पर पड़ी, जिस पर दो युवक सवार थे। उन्हें आशंका है कि बाइक पर पीछे बैठा युवक चलती ट्रक पर चढ़ गया, जबकि दूसरा बाइक चलाता रहा। इसी दौरान तिरपाल काटकर माल नीचे फेंका गया और दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि अंधेरा होने और वाहन की गति अधिक होने के कारण वे आरोपियों की पहचान नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि घटना के समय अंधेरा होने लगा था।

यदि वे तत्काल ट्रक रोकते तो उनके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना, लूटपाट या हमला भी हो सकता था। इसी कारण उन्होंने बीच रास्ते वाहन नहीं रोका और सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के बाद मामले की जानकारी ली। वहां पहुंचकर देखा तो तिरपाल कटी हुई थी और दो कट्टे गायब थे। राजेश कोहली का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उनकी ट्रक से इसी प्रकार पांच कट्टे चोरी हो चुके हैं। उनका आरोप है कि पिपलिया-मल्हारगढ़ हाईवे पर इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कई ट्रकों से रोज सामान उतरता है। विशेष रूप से बाहर से आने वाले ट्रक चालक कई बार यह समझ ही नहीं पाते कि रास्ते में उनकी चलती ट्रक से माल चोरी हो चुका है। बदमाश बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से हाईवे पर लगातार गश्त बढ़ाने, संदिग्ध वाहनों एवं बाइक सवारों की सघन जांच करने तथा सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सक्रिय गिरोह का पता लगाने की मांग की है।

उनका कहना है कि यदि समय रहते इस गिरोह पर कार्रवाई नहीं हुई तो परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और हाईवे पर माल परिवहन करने वाले चालक असुरक्षित महसूस करेंगे। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद जब वे शिकायत दर्ज कराने संबंधित पुलिस थाने पहुंचे तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा उनकी शिकायत दर्ज कराने की मांग की है। इधर क्षेत्र के परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से हाईवे पर चलती ट्रकों से सामान चोरी होने की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में पुलिस को इस ओर विशेष ध्यान देकर रात्रिकालीन गश्त बढ़ानी चाहिए, ताकि ऐसे गिरोहों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और परिवहन व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

1239 किलो डोडाचूरा की तस्करी के मुख्य आरोपी सुभाष गुर्जर को 10 वर्ष की सश्रम कैद, एक लाख अर्थदंड लगाया

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, एन.डी.पी.एस. एक्ट मंदसौर आलोक प्रतापसिंह द्वारा प्र.कं.-53/2017 एन.सी.बी. इंदौर विरूद्ध सुभाष गुर्जर, आदि में घोषित निर्णय दिनांक 07.07.2026 में आरोपी सुभाष गुर्जर पिता राजाराम गुर्जर निवासी अफजलपुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन की कहानी अनुसार भारत संघ गृह मंत्रालय दिल्ली यूनिट स्वापक नियंत्रण ब्यूरो झोनल इकाई एन.सी.बी. इंदौर के द्वारा दिनांक 13.05.2017 के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में पदस्थ आसूचना अधिकारी ने एक गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुवे मंदसौर एमआईटी कॉलेज के पास बालाजी राजस्थानी ढाबे पर एक टाटा कंपनी की ट्रक क्र. आरजे 19 आईजी 9090 की तलाशी लेने पर सोयाबीन के आटे की बोरियों के नीचे छिपाया गया 1239.765 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा आरोपी के सचेतन आधिपत्य से जब्त किया गया।

जिसका अपराध क्र.-1/17 पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान अवैध डोडाचूरा मंदसौर से पंजाब अवैध परिवहन किये जाने सम्बंधित जानकारी प्राप्त हुई अनुसंधान अधिकारी द्वारा माननीय विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. एक्ट मंदसौर के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक मनीष दादूपंथी द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।

सम्पादकीय

डेटा पर नियंत्रण करने वाले ही तय करेंगे भविष्य, भारत के सामने बड़ी चुनौती

जनवरी में टिकटॉक विवाद को सुलझाने का डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन का निर्णय आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के युग में डेटा संप्रभुता के विरोधाभास को उजागर करता है। उस निर्णय ने अमेरिकी कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय दोनों द्वारा समर्थित रुख को पलट दिया। हालांकि बाइटडांस ने अपनी हिस्सेदारी निर्धारित सीमा से कम कर दी और अमेरिकी उपयोगकर्ताओं का डेटा ऑरेकल के क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में स्थानांतरित कर दिया गया, फिर भी उसने टिकटॉक के अनुशंसा एल्गोरिद्म पर नियंत्रण बनाए रखा, जो यह निर्धारित करता है कि अमेरिकी क्या देखते हैं, वे कितनी देर तक जुड़े रहते हैं और उनके व्यवहार को किस तरह से आकार मिलता है।

इस समझौते से डेटा के भंडारण का स्थान तो बदल गया, लेकिन उससे जानकारी निकालने वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि एक बार किसी विदेशी प्लेटफॉर्म के किसी राष्ट्र के समाज में गहराई से समाहित हो जाने के बाद डिजिटल संप्रभुता को पुनः प्राप्त करना कितना कठिन हो जाता है।

टिकटॉक प्रकरण डेटा के लिए चल रही एक व्यापक वैश्विक प्रतिस्पर्धा की झलक दिखाता है, जिसके परिणाम हमारे समय की किसी भी सैन्य प्रतिद्वंद्विता के समान महत्त्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। विशाल डेटासेट का उपयोग करने वाले राष्ट्र एआई प्रणालियों के विकास में निर्णायक बढ़त हासिल करेंगे जो अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को आकार देती हैं। लेकिन दांव केवल एआई तक ही सीमित नहीं हैं। जनसंख्या-स्तरीय व्यवहार संबंधी डेटा तक पहुंच रखने वाली कोई विदेशी खुफिया एजेंसी सामाजिक विभाजन और व्यवहार संबंधी कमजोरियों की पहचान कर सकती है, जिससे सोशल इंजीनियरिंग हमले कहीं अधिक प्रभावी हो जाते हैं।

वैश्विक डेटा परिदृश्य के दो अलग-अलग स्तर हैं। पहला है अमेरिका-चीन का एकाधिकार। दूसरा स्तर उन मध्यम शक्तियों का है जो एकाधिकार पर अपनी निर्भरता कम करते हुए डेटा संप्रभुता रणनीतियों को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। अन्य देश संप्रभु विकल्पों के लिए आवश्यक निवेश विकसित करना अभी शुरू ही कर रहे हैं।

पिछले एक दशक में चीन ने डेटा को एक रणनीतिक संपत्ति में बदल दिया है। इसने भूमि, श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त डेटा को उत्पादन के पांचवें कारक के रूप में मान्यता दी है, राष्ट्रीय डेटा प्रशासन की स्थापना की है और डेटा की कुछ श्रेणियों को कंपनियों की बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में मान्यता देने की अनुमति दी है। इसके साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून डेटा के स्थानीयकरण के माध्यम से संप्रभु नियंत्रण को मजबूत करते हैं, जबकि राष्ट्रीय खुफिया कानून राज्य को डेटा तक पहुंच प्रदान करता है।

चीन के विपरीत, अमेरिका ने बाजार-आधारित नवाचार के माध्यम से डेटा के क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाई है। अमेरिकी कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और सोशल मीडिया पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं, जिनके माध्यम से दुनिया की अधिकांश डिजिटल गतिविधियां संचालित होती हैं। हालांकि, इसका रणनीतिक प्रभाव समान है- वैश्विक डेटा जिस बुनियादी ढांचे पर मौजूद है, उस पर नियंत्रण।

क्लाउड ऐक्ट के तहत अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने नियंत्रण में मौजूद डेटा, चाहे वह भौतिक रूप से कहीं भी संग्रहीत हो, अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि डेटा संप्रभुता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि डेटा कहां स्थित है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्लेटफॉर्म को कौन नियंत्रित करता है।

विदेशी डिजिटल अवसंरचना पर दीर्घकालिक निर्भरता आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा करती है, जिसकी वजह से देश डेटा संप्रभुता के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं। इससे चार महत्त्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली, डेटा संप्रभुता अब केवल नियामक नहीं बल्कि भू-राजनीतिक मुद्दा बन गई है। दूसरी, एक बार विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म गहराई से स्थापित हो जाने पर संप्रभुता को पुनः प्राप्त करना कठिन हो जाता है। तीसरी, केवल डेटा का स्थानीयकरण ही पर्याप्त नहीं है; डेटा से जानकारी निकालने वाले एल्गोरिदम पर नियंत्रण भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। अंत में, प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है और कार्रवाई करने का समय अब ??आ गया है।

भारत, जिसे विश्व का सबसे बड़ा डेटा उत्पादक माना जा सकता है, अमेरिकी प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक का भुगतान प्रणालियों के लिए 2018 का डेटा स्थानीयकरण निर्देश और डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने की योजनाएं वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े रहते हुए डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के देश के दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। डीपीडीपी अधिनियम, 2023, गोपनीयता, संप्रभु निगरानी और अंतरराष्ट्रीय डेटा प्रवाह को संतुलित करते हुए एक सुविचारित दृष्टिकोण अपनाता है। भारत का सबसे मौलिक योगदान डेटा सशक्तीकरण एवं संरक्षण आर्किटेक्चर/अकाउंट एग्रीगेटर (डीईपीए) ढांचा है। पारंपरिक प्लेटफार्म मॉडल के विपरीत, जहां कंपनियां उपयोगकर्ता डेटा से उत्पन्न अधिकांश आर्थिक मूल्य पर कब्जा कर लेती हैं, डीईपीए व्यक्तियों को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए अपने डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने में सक्षम बनाता है। सिलिकॉन वैली ने डेटा का मुद्रीकरण करने वाले प्लेटफॉर्म बनाए, यूरोप ने डेटा पर अधिकारों को मजबूत किया और चीन ने राज्य के नेतृत्व वाले डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया। भारत ने एक ऐसे मॉडल का नेतृत्व किया है जहां व्यक्ति अपने डेटा को नियंत्रित करते हैं।

उच्चतर विकसित अस्तित्व का निर्माण करता है सहजयोग

सहजयोग ध्यान से व्यक्ति के व्यक्तित्व में किस प्रकार परिवर्तन आता है इसका वर्णन श्री माताजी निर्मला देवी जी ने अपनी अमृतवाणी में इस प्रकार किया है, सहजयोग एक ऐसी अभिनव चीज़ है, जो आपकी वास्तविकता को आपके अंदर स्थापित करता है, जिसके कारण आप सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी वास्तविकता ही बहुत सुन्दर है। यह आनंददायक है, और तब आप इससे दूर भागना नहीं चाहते। यही वो बात है जिसे हमें समझना है, कि हम यहाँ अपनी वास्तविकता को पाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए आए हैं। अपने आप को जानने से, कितनी चीज़ें हमारे साथ घटित हो सकती हैं? आपको शायद इसका अनुमान नहीं है। यह पूरी संपदा जो आप हैं, पूरा वैभव जो आप हैं, पूरी सुंदरता जो आप हैं, यह सब आपकी अपनी हो जाती है। आप अपने जीवन के स्वामी बन जाते हैं आप एक अलग तरह के व्यक्ति बन जाते हैं। आप एक उच्चतर विकसित जीवात्मा बन जाते हैं। और तब आप महसूस करते हैं कि आप अचानक एक ऐसे अस्तित्व बन गए हैं, जो सामूहिक रूप से जागृत है।

अपनी उपस्थिति से, आप दूसरों को परिवर्तित करना आरंभ कर देते हैं। अपने अस्तित्व से आप दूसरे लोगों को बदलना शुरू करते हैं। आप वातावरण को, और नकारात्मकता की सूक्ष्म समस्याओं को परिवर्तित करने लगते हैं। यह सब उस पेड़ की तरह से कार्यान्वित होता है, जिस तरह से एक वृक्ष फलता-फूलता है। बहार की यह सुगंध अपने चारों ओर एक अलग तरह का आभामंडल बनाती है, जिससे यह अपने आस पास की सभी मधुमक्खियों को शहद इकट्ठा करने के लिए आकर्षित करती है। इसी तरह, जब एक व्यक्ति आत्मसाक्षात्कारी बनता है, आलोकित होता है, उसका आभामंडल निखर उठता है, और वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है।

सम्मान नहीं, रणनीतिक विश्वास की मुहर है बिंतांग आदिपूर्णा

कूटनीति की असली ताकत हाथ मिलाने, औपचारिक स्वागत या साझा तस्वीरों में नहीं, बल्कि उस विश्वास में दिखाई देती है, जिसे कोई राष्ट्र अपने सर्वोच्च सम्मान के जरिए सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया जाना ऐसा ही ऐतिहासिक क्षण था। फाइटर जेट्स की सलामी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के आत्मीय स्वागत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत-इंडोनेशिया संबंध अब केवल साझा सांस्कृतिक विरासत तक सीमित नहीं हैं। यह सम्मान दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास, साझा भविष्य और क्षेत्रीय जिम्मेदारियों की नई साझेदारी का प्रतीक है। सदियों पुरानी मित्रता अब रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग जैसे नए आधारों पर कहीं अधिक सशक्त होकर उभर रही है।

बिंतांग आदिपूर्णा स्वीकार करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे 140 करोड़ भारतीयों के नाम कर दिया। यही उस सम्मान का सबसे बड़ा अर्थ भी था। स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू (1995 में मरणोपरांत) के बाद वे दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। वर्ष 1959 में स्थापित यह अलंकरण उन व्यक्तित्वों को दिया जाता है, जिन्होंने इंडोनेशिया की एकता, स्थिरता और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। किसी विदेशी नेता का इससे सम्मानित होना भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, विश्वसनीय नेतृत्व और दोनों देशों के बीच गहरे होते रणनीतिक विश्वास का प्रमाण है। गणतंत्र दिवस 2025 पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की भारत यात्रा के बाद हुआ यह जवाबी दौरा भी स्पष्ट करता है कि भारत-इंडोनेशिया संबंध अब केवल औपचारिक कूटनीति नहीं, बल्कि परिणाम देने वाली रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं।

इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि रक्षा सहयोग रही, जिसने भारत-इंडोनेशिया संबंधों को नई रणनीतिक ऊंचाई दी। दोनों देशों के बीच हुए 16 समझौतों में रक्षा क्षेत्र सबसे अहम रहा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त बैटरियों की खरीद, एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल से जुड़े समझौते और संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं ने साबित कर दिया कि भारत अब केवल हथियार आयातक नहीं, बल्कि विश्वसनीय रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदार बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में एस्ट्रा मिसाइल के युद्ध-प्रमाणित प्रदर्शन ने इंडोनेशिया का भरोसा और मजबूत किया। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया का ब्रह्मोस से जुड़ना भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी। ये समझौते केवल हथियारों के सौदे नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक संतुलित, सक्षम और मजबूत बनाने की दिशा में निर्णायक कदम हैं।

रणनीतिक दृष्टि से साबांग पोर्ट का संयुक्त विकास इस यात्रा की सबसे दूरगामी उपलब्धियों में है। मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित यह बंदरगाह वैश्विक समुद्री व्यापार का अहम केंद्र है और ग्रेट निकोबार परियोजना से इसकी निकटता भारत के लिए इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। इससे समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, नौवहन और व्यापारिक लॉजिस्टिक्स में दोनों देशों की क्षमता मजबूत होगी। वहीं, निकल, स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट्स जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश पर सहमति भविष्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक कदम है। दुनिया के सबसे बड़े निकल उत्पादक इंडोनेशिया और ईवी व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बढ़ते भारत की यह साझेदारी चीन-निर्भर आपूर्ति श्रृंखला का प्रभावी विकल्प बन सकती है। यही सहयोग ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता की मजबूत बुनियाद भी रखेगा। डिजिटल सहयोग ने इस यात्रा को भविष्य की शासन व्यवस्था से जोड़ दिया। भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता इस दौरे में भी साफ दिखाई दी। यूपीआई के विस्तार, इंडोनेशिया के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित करने और आईआईएम बेंगलुरु के साथ प्रबंधन व प्रशासनिक क्षमता निर्माण पर हुए समझौते आधुनिक सुशासन की नई दिशा दिखाते हैं। वहीं, इसरो-बीआरआईएन के बीच अंतरिक्ष सहयोग तथा कृषि, स्वास्थ्य, दूरसंचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े समझौते बताते हैं कि भारत-इंडोनेशिया संबंध अब पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर नवाचार, प्रौद्योगिकी, ज्ञान और मानव संसाधन विकास पर आधारित व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं, जिसका लाभ आने वाले वर्षों में दोनों देशों को मिलेगा।

मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में यह साझेदारी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंद-प्रशांत आज रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का प्रमुख केंद्र है। ऐसे दौर में स्वतंत्र, खुला और समृद्ध हिंद-प्रशांत के प्रति भारत और इंडोनेशिया का साझा संकल्प पूरे क्षेत्र को स्थिरता का सकारात्मक संदेश देता है। रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े समझौते इस दृष्टि को ठोस आधार देते हैं। लगभग 24 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को अधिक संतुलित और व्यापक बनाने की दिशा में भी यह यात्रा महत्वपूर्ण साबित होगी। आर्थिक सहयोग, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने वाले समझौते दोनों देशों के लिए नए अवसरों के साथ एशिया में संतुलित और टिकाऊ विकास की संभावनाओं को भी सुदृढ़ करते हैं।

दरअसल, यह यात्रा केवल एक सफल राजनयिक दौरा नहीं, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर दृष्टि को नई दिशा देने वाला निर्णायक पड़ाव है। रामायण, प्रंबनन मंदिर और साझा सांस्कृतिक विरासत से जुड़े ऐतिहासिक रिश्ते अब रक्षा प्रौद्योगिकी, डिजिटल अवसंरचना, समुद्री सहयोग और आर्थिक लचीलेपन की आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने साबित किया कि दूरदर्शी कूटनीति केवल वर्तमान की चुनौतियों का समाधान नहीं करती, बल्कि भविष्य की संभावनाओं की भी मजबूत नींव रखती है। बिंतांग आदिपूर्णा महज़ एक सम्मान नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास का प्रतीक है, जिस पर भारत और इंडोनेशिया आने वाले दशकों की नई साझेदारी गढ़ रहे हैं। यह रिश्ता अब केवल भावनात्मक निकटता नहीं, बल्कि साझा हितों, रणनीतिक भरोसे, संयुक्त क्षमताओं और क्षेत्रीय उत्तरदायित्व पर आधारित है। यही साझेदारी दोनों देशों को एशिया ही नहीं, वैश्विक मंच पर भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती है।

-प्रो. आरके जैन

एथनॉल नीति में उपभोक्ता विकल्प और आर्थिक संतुलन की जरूरत

भारत का एथनॉल-मिश्रण कार्यक्रम एक अप्रत्याशित विवाद का विषय बन गया है। इसके उद्देश्य को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। यह सही है कि पेट्रोल में 20 फीसदी एथनॉल मिलाने से आयातित क?च्चे तेल पर निर्भरता कम होती है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा बेहतर होती है और देश के स्वच्छ ईंधन लक्ष्यों को मदद मिलती है। लेकिन हालिया विवाद ई20 (20 फीसदी एथनॉल मिश्रण) को लेकर है और यह स्वयं एथनॉल मिश्रण पर नहीं बल्कि इसे लागू किए जाने के तरीके पर केंद्रित है। सरकार ई20 के बचाव में तमाम साक्ष्य पेश कर रही है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), इंडियन ऑयल और वाहन विनिर्माताओं के तकनीकी अध्ययनों में उच्च एथनॉल मिश्रण से व्यापक इंजन क्षति या उसमें गंभीर रूप से जंग लगने का कोई संकेत नहीं मिल सका है।

साथ ही अध्ययनों ने यह भी स्वीकार किया कि वाहन मालिकों को हो रहे अनुभव भी गलत नहीं हैं। पहला, एथनॉल का कम उष्मीय मान (कैलोरिफिक वैल्यू) ईंधन की दक्षता को कम करता है जिससे उनके माइलेज में कमी आती है। दूसरा, पुराने वाहनों के कुछ कलपुर्जे ई20 के कारण तेजी से खराब हो सकते हैं। अध्ययनों ने यह भी संकेत किया कि पुरानी ईंधन प्रणालियों में लगे रबर के कुछ कलपुर्जे ई20 के साथ कमजोर प्रदर्शन करते हैं और समय के साथ उन्हें बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है।

देश की सड़कों पर इस समय करोड़ों ऐसे वाहन हैं जो ई20 के लिए अनुकूल इंजन और फ्यूल सिस्टम बनने के पहले से चल रहे हैं। इन वाहनों के मालिकों के पास अब उस ईंधन का प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो उनके वाहनों के अनुकूल है ही नहीं। पुराने वाहनों के मालिकों को इस ऊर्जा बदलाव की लागत उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है जबकि उन्हें कोई सार्थक विकल्प नहीं दिया गया। यदि ई20 के साथ-साथ ई10 की उपलब्धता जारी रहती तो नए मानक से पहले बने वाहनों वाले उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बहुत कम पड़ता।

एथनॉल की मात्रा में भविष्य में किसी भी वृद्धि के लिए ऑटो विनिर्माताओं को आवश्यक समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। ब्राजील जैसे एथनॉल का इस्तेमाल करने वाले परिपक्व बाजारों ने दिखाया है कि उपभोक्ताओं को अलग-अलग ईंधन विकल्प देना महत्त्वाकांक्षी मिश्रण लक्ष्यों के साथ पूरी तरह संगत है। 1975 में एल्कोहल समर्थक कार्यक्रम की शुरुआत से, उस देश को एक स्थिर ई20 पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में पांच दशकों से अधिक का समय लगा, और अब वहां मानक ई30 पेट्रोल मिश्रण चलता है। वास्तव में ब्राजील ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को अपनाने में तेजी लाई जिससे मोटर चालकों को ईंधन पंप पर जो भी ईंधन सस्ता हो, उसे चुनने की स्वतंत्रता मिली। एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

-सुनील कुमार महला

हिंद-प्रशांत में भारत का बढ़ता सामर्थ्य एवं साझेदारियां

भारत आज केवल विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने जिस आत्मविश्वास, स्पष्टता और दूरदृष्टि का परिचय दिया है, उसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी है। कभी जो भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशी हथियारों पर निर्भर था, वही भारत आज आधुनिक मिसाइलों, रक्षा प्रणालियों और सैन्य उपकरणों का निर्यात करने वाला विश्वसनीय राष्ट्र बन चुका है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक, वैज्ञानिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति का भी प्रमाण है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया सहित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ हुई उच्चस्तरीय वार्ताएं इस नई विदेश नीति की सफलता का सशक्त उदाहरण हैं। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्रों में हुए समझौते यह स्पष्ट करते हैं कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है।

भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है। वर्षों तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक माना जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल रही है। 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान ने रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, पिनाका रॉकेट सिस्टम, तेजस लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक रक्षा उपकरण आज विश्व के अनेक देशों का विश्वास जीत रहे हैं। भारत की स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल आज केवल भारतीय सेना की शक्ति का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि विश्व के अनेक देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम भी बन रही हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवाद विरोधी अभियानों में इन हथियारों की प्रभावशीलता ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। यही कारण है कि इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण देश अपने सुखोई लड़ाकू विमानों के लिए अस्त्र मिसाइल प्राप्त करना चाहते हैं तथा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत के रक्षा उद्योग के प्रति बढ़ते वैश्विक विश्वास का प्रमाण है।

इंडोनेशिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। मलक्का जलडमरूमध्य जैसे विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पर उसकी रणनीतिक स्थिति वैश्विक व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग केवल दो देशों के संबंधों को मजबूत नहीं करता, बल्कि पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी नया आयाम देता है। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से दोनों देशों का सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत अब किसी पर निर्भर होकर नहीं, बल्कि समान साझेदारी और परस्पर सम्मान के आधार पर संबंध स्थापित कर रहा है। भारत किसी देश पर अपनी शक्ति थोपने में विश्वास नहीं रखता। उसकी विदेश नीति का मूल मंत्र है-'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' और 'विश्व बंधुत्व'। यही कारण है कि भारत जहां अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है, वहीं दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ भी विश्वासपूर्ण साझेदारी विकसित कर रहा है।

आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व राजनीति का केंद्र बन चुका है। चीन का विस्तारवादी रवैया, दक्षिण चीन सागर में उसका सैन्यीकरण, छोटे देशों पर दबाव बनाने की नीति तथा आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। भारत ने इन परिस्थितियों में संतुलित, शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ रणनीति अपनाई है। भारत किसी के विरुद्ध युद्ध नहीं चाहता, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से कोई समझौता भी नहीं करता। यही संतुलित दृष्टिकोण भारत को विश्व का विश्वसनीय साझेदार बनाता है। भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए स्पष्ट संदेश है कि नया भारत अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। भारत अब केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आधुनिक तकनीकी युद्ध की तैयारियों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन इस दिशा में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं की सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि उन्होंने भारत की वैश्विक छवि को अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान की है। आज विश्व के बड़े राष्ट्र भारत को केवल विशाल बाजार के रूप में नहीं, बल्कि विश्वसनीय मित्र, तकनीकी साझेदार, निवेश गंतव्य और सुरक्षा सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। जी-20 की सफल अध्यक्षता, क्वाड की सक्रिय भूमिका, इंडो-पैसिफिक सहयोग, वैश्विक दक्षिण की आवाज तथा जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भारत का नेतृत्व इसकी पुष्टि करता है। भारत की विदेश नीति अब केवल कूटनीतिक दस्तावेज नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय विकास का सशक्त माध्यम बन चुकी है। रक्षा निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है, लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, अनुसंधान एवं नवाचार को नई गति मिल रही है और भारतीय उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत हो रहे हैं। यह विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र सदैव शांति, सह-अस्तित्व और परस्पर सम्मान रहा है। आदर्श स्थिति में किसी भी दो देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की नींव किसी तीसरे देश के प्रति वैमनस्य या शत्रुता पर नहीं, बल्कि साझा विकास, सुरक्षा और स्थिरता पर आधारित होनी चाहिए। किंतु अंतरराष्ट्रीय राजनीति आदर्शों से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों और शक्ति-संतुलन से संचालित होती है। आज चीन और पाकिस्तान अपने सैन्य एवं आर्थिक गठजोड़ को सऊदी अरब तक विस्तार देने के प्रयासों में जुटे हैं। हाल के सप्ताहों में सऊदी नेतृत्व और बीजिंग के बीच बढ़ती सक्रियता इस बदलते भू-राजनीतिक समीकरण का संकेत है। यद्यपि सऊदी अरब की प्राथमिक सुरक्षा चिंताएं पाकिस्तान और चीन से अलग हैं तथा उसका प्रमुख ध्यान खाड़ी क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव पर केंद्रित है, फिर भी बदलते वैश्विक समीकरण भारत के लिए सतर्क रहने का संदेश देते हैं। पाकिस्तान हर परिस्थिति में भारत के विरुद्ध रणनीतिक लाभ उठाने का अवसर तलाशता है, जबकि चीन अपने विस्तारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी, संतुलित और सक्रिय विदेश नीति भारत के हितों की प्रभावी सुरक्षा करती दिखाई देती है। उनकी कूटनीति केवल मित्र देशों के साथ विश्वास बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन और पाकिस्तान की शरारतों, षड्यंत्रों तथा सामरिक चुनौतियों का संयमित और दृढ़ता से सामना करने की क्षमता भी प्रदर्शित करती है। यही दूरगामी सोच भारत को एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। आज विश्व एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो शक्ति और शांति, विकास और सुरक्षा, तकनीक और मानवता के बीच संतुलन स्थापित कर सके। भारत इस भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह सिद्ध किया है कि सशक्त राष्ट्र वही होता है जो अपनी रक्षा करने में सक्षम होने के साथ-साथ विश्व शांति और मानव कल्याण का भी वाहक बने। निस्संदेह भारत अब विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का प्रतीक है। वह हथियारों का निर्माण युद्ध भड़काने के लिए नहीं, बल्कि शांति की रक्षा और संतुलन स्थापित करने के लिए कर रहा है। यही भारत की सांस्कृतिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्व की पहचान है। आने वाले वर्षों में भारत की यही संतुलित विदेश नीति, आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति और विश्वसनीय कूटनीतिक नेतृत्व न केवल विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेगा, बल्कि विश्व व्यवस्था को भी अधिक सुरक्षित, संतुलित और न्यायपूर्ण दिशा प्रदान करेगा।

-ललित गर्ग

भारत को ग्लोबल कैपिटल चाहिए तो FTA को निवेश के लिहाज से बनाना होगा मजबूत

यह उत्साहित करने वाली बात है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) द्वारा संचालित आधुनिक कारोबार में व्यापार और निवेश के मौलिक संबंध को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के वार्ताकारों द्वारा मान्यता मिलनी शुरू हो गई है। भारत ने हाल ही में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) की विकसित अर्थव्यवस्थाओं और न्यूजीलैंड के साथ जो मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, उनमें निवेश से जुड़े प्रावधानों को साफ तौर पर शामिल किया गया है। यद्यपि ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों एफटीए में निवेश संबंधी अध्याय केवल प्रोत्साहन, सहयोग और सुविधा से जुड़े प्रावधानों को शामिल करते हैं।

निवेशक संरक्षण और निवेश विवाद निपटान तंत्र जैसे महत्वपूर्ण पहलू इन एफटीए में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा ईएफटीए और न्यूजीलैंड के साथ एफटीए में क्रमशः 100 अरब डॉलर और 20 अरब डॉलर का निवेश लक्ष्य साझेदार देशों के 'सर्वोत्तम प्रयासों' पर आधारित है। यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लक्ष्य हासिल नहीं होता तो पुनर्संतुलन तंत्र केवल 15 वर्षों के बाद लागू होगा और तब भी यह परामर्श और संभावित कारणों पर विचार की प्रक्रिया प्रदान करता है।

प्रभावी रूप से देखें तो निवेश प्रतिबद्धता एफटीए के लागू होने के कम से कम 15 वर्षों तक विस्तारित हो सकती है। इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि ब्रिटेन (यूके) और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ अपेक्षाकृत गहरे एफटीए में निवेश अध्याय या निवेश उदारीकरण और सुविधा से जुड़े प्रावधान शामिल नहीं हैं और अब तक इन देशों के साथ कोई निवेश समझौता/संधि भी मौजूद नहीं है।

भारत की तुलना में अन्य विकासशील और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा है। विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और व्यापारिक खींचतान के बावजूद अपनी मजबूती बनाए रखी है और लगातार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) की 'आसियान निवेश रिपोर्ट-2025' के अनुसार वर्ष 2021 से आसियान विकासशील क्षेत्रों में एफडीआई प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र, खासकर आपूर्ति श्रृंखला आधारित उद्योग इस सफलता के प्रमुख आधार रहे हैं। इस क्षेत्र में वियतनाम रिकॉर्ड एफडीआई के साथ सबसे बड़े निवेश प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा है।

वियतनाम के बाद अब थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया जैसे अन्य आसियान देश भी यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर बातचीत कर रहे हैं। वहीं इंडोनेशिया ने वर्ष 2025 में यूरोपीय संघ के साथ अपने एफटीए और आईपीए दोनों पर वार्ता पूरी कर ली है। इसके अलावा उसने वर्ष 2024 में सीपीटीपीपी की सदस्यता के लिए भी आवेदन किया है।

ध्यान देने वाली बात है कि आसियान ने अपने क्षेत्रीय वस्तु व्यापार समझौते के तहत लगभग 100 फीसदी शुल्क उदारीकरण हासिल कर लिया है। वर्ष 2020 से उसने गहन बड़े-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय एफटीए में भागीदारी के माध्यम से अपने निवेश को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। चार आसियान अर्थव्यवस्थाएं वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई विशाल क्षेत्रीय समझौते सीपीटीपीपी की सदस्य हैं। सीपीटीपीपी में संचयन-आधारित मूल स्रोत नियम शामिल हैं जो आपूर्ति श्रृंखला गहन निवेश को आकर्षित करने में सहायक हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) को आसियान निवेश समझौते और आसियान निवेश सुविधा ढांचे के कार्यान्वयन द्वारा पूरक किया गया है। द्विपक्षीय पहलों में वियतनाम ने पिछले दशक में कई गहन एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। 90 फीसदी से अधिक शुल्क उदारीकरण के अलावा उसके एफटीए की गहराई बौद्धिक संपदा-संबंधी प्रावधानों और तकनीकी मानकों में रही है जिसने उसके घरेलू नियामक ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सुधारों को गति दी है। इसके अतिरिक्त, निवेश उदारीकरण और निवेशक-सुरक्षा प्रावधानों का समावेश वियतनाम को चीन से दूर विविधीकरण कर रही कई बड़ी कंपनियों के लिए उत्पादन और निर्यात आधार के रूप में अधिक आकर्षक बनाने में मददगार रहा है।

प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में अपने एफडीआई प्रवाह को बढ़ाने के लिए भारत को अपने एफटीए की गहराई बढ़ानी होगी। इस उद्देश्य की ओर, सबसे पहले उसे बजट 2025 में घोषित शुल्कों की व्यापक समीक्षा का कार्य तेज करना चाहिए। महत्त्वपूर्ण आयातित कच्चे माल पर शुल्क में कमी भारत को अपनी विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और निर्यात-उन्मुख एफडीआई आकर्षित करने में मदद करेगी।

दूसरा, भारत को यूरोपीय संघ के साथ आईपीए पर बातचीत कर उसे अंतिम रूप देना चाहिए। आईपीए की पुष्टि प्रक्रिया लंबी होती है और इसे संगठन के सदस्य देशों के स्तर पर किया जाता है, इसलिए लक्ष्य यह होना चाहिए कि आईपीए वार्ता को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि निवेश विवाद निपटान तंत्र और निवेशक-सुरक्षा प्रावधानों को इस तरह डिजाइन किया जाए कि वे भारत की भविष्य की एफटीए और आईपीए वार्ताओं के लिए एक मानक बन जाएं।

यूरोपीय संघ के निवेश समझौतों का सिंगापुर, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन भारत के लिए निवेशक-सुरक्षा और राज्य-संप्रभुता प्रावधानों के उपयुक्त संयोजन पर काम करने का एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। यह विशेष रूप से उपयोगी होगा क्योंकि भारत कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापक व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।

-धनंजय राजौरा

जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी

निजामड़ी का शासकीय स्कूल भवन हो रहा जर्जर, अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे परिजन

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के ग्राम निजामड़ी स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है जो कभी भी धराशायी हो सकता है। लगातार हो रही बारिश में छत से टपकते पानी की एक-एक बूंद बच्चों के डर का कारण बन रही है। विद्यालय भवन की दयनीय हालत देखते हुए अब अभिभावक भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में घबरा रहे हैं कि कहीं उनके बच्चे के साथ कोई हादसा न हो जाए।

इस विद्यालय में कक्षा पहली से पांचवीं तक के बच्चे अध्ययनरत हैं जो पूरी तरह जर्जर हो चुके भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यह स्थिति सरकार की शिक्षा सुधार योजनाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की बदहाली को दर्शाती है। हालात यह हैं कि विद्यालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। बारिश के दौरान छत से लगातार पानी टपकता है, जिससे कक्षाओं में पढ़ाई बाधित होती है। भवन की छत में लगे सरिए बाहर निकल आए हैं, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। स्कूल में पीने के पानी और उपयोग योग्य शौचालय की भी उचित व्यवस्था नहीं है। बारिश के कारण विद्यालय का रिकार्ड भीगकर खराब हो गया है।

पहले 17 बच्चे पढ़ते थे, अब रह गए केवल 8- विद्यालय प्रबंधन खुद इस बात से दुखी है, जिनका कहना है कि कई बार भवन की स्थिति के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है। भवन को डिस्मेंटल करने के आदेश भी जारी हुए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले विद्यालय में 17 विद्यार्थी थे, लेकिन अब केवल 8 बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है। शिक्षिकाएं भी जर्जर कमरों में बैठने से कतराती हैं, क्योंकि उन्हें हर समय छत गिरने की आशंका बनी रहती है। खुद बच्चों ने शासन से मांग की है कि अब तो उनके विद्यालय भवन की सुध ली जाए और इसकी जगह नया भवन बनाया जाए। यही नहीं जर्जर भवन और बारिश के मौसम में सांप-बिच्छू निकलने का खतरा बना रहता है, जिससे बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो गया है।

इनका कहना है- मामला हमारे संज्ञान में है। इसकी जांच कराई जाएगी। तब तक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए फिलहाल विद्यालय को गांव की आंगनवाड़ी भवन में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।

- दीपा किर, जिला शिक्षा अधिकारी-शाजापुर

ई-अटेंडेंस के लिए उफनता नाला पार कर स्कूल पहुंचे टीचर

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के मोहन बड़ोदिया विकासखंड में भारी बारिश के कारण शिक्षकों को जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। एकीकृत शासकीय हाई स्कूल नौलाया के पास स्थित नाले में पानी भरने से मुख्य मार्ग जलमग्न हो गया है। शासन की ई-अटेंडेंस व्यवस्था के चलते शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करनी होती है। बुधवार को स्कूल के प्राचार्य गोकुल प्रसाद कुलमिया और अन्य स्टाफ सदस्य उफनता नाला पार करते हुए विद्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि बारिश के दौरान नाले का पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे आवागमन बेहद खतरनाक हो जाता है। इसके बावजूद, वे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन खतरा उठाकर स्कूल आ रहे हैं। ग्रामीणों की माने तोयह समस्या हर साल बारिश के मौसम में होती है। नाले पर सुरक्षित पुल या वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण शिक्षक, विद्यार्थी और स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल मार्ग पर शीघ्र ही पुलिया का निर्माण कराया जाए या सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि इससे भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सकेगा और शिक्षा व्यवस्था भी सुचारु रूप से चल पाएगी।

आपदा प्रबंधन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए - कलेक्टर श्रीमती चौहान

ग्वालियर/दैनिक मालवा हेराल्ड। ग्वालियर जिले में आपदा प्रबंधन के लिये विभागीय अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन जिम्मेदारियों का मुस्तैदी के साथ पालन हो ताकि आपदा प्रबंधन के समय आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जिला स्तर से आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम भी गठित किया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर 0751-2446232 है। कंट्रोल रूम के माध्यम से भी जिले की जानकारी संकलित की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में आपदा प्रबंधन के संबंध में जिले में किए गए प्रबंधन की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

स्टॉप डायरिया अभियान के तहत पेयजल स्रोतों में कराया जा रहा क्लोरीनेशन जल गुणवत्ता पर विशेष निगरानी

राजगढ़/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में जिले के सभी पेयजल स्त्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पेयजल स्त्रोतों के आसपास गंदगी न हो तथा वे प्रदूषित न हों, इसके लिए पेयजल स्त्रोतों में क्लोरीनेशन कराया जा रहा है। स्टॉप डायरिया अभियान 16 जून से 30 जुलाई के अंतर्गत कलेक्टर डॉ. मिश्रा के निर्देशन में जिले के तीनों उपखंडों में विभागीय अमले को खंडवार कार्यपालन यंत्री श्री हरम सिंह बामणिया एवं जिला भूजल वैज्ञानिक डॉ. रामगोपाल नागर द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपखंड कार्यालयों में पहुंचकर विकासखंडवार हैंडपंप टेक्नीशियनों की बैठक लेकर प्रत्येक हैंडपंप तथा कुआं-बावड़ी जैसे पेयजल स्त्रोतों में क्लोरीनेशन कराने एवं पेयजल स्त्रोतों के आसपास प्रदूषण नहीं होने देने के संबंध में समीक्षा की जा रही है।

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत पेयजल स्त्रोतों को दीर्घायु बनाने के उद्देश्य से रिचार्ज पिट एवं रिचार्ज शॉफ्ट का निर्माण कराया गया है। सभी भूजल संवर्धन संरचनाओं के आसपास गंदगी न हो तथा दूषित नालियों का पानी जल संरचनाओं में नहीं पहुंचे और पेयजल स्त्रोत प्रदूषित न हों, इसके लिए सभी मैदानी उपयंत्रियों, विकासखंड समन्वयकों एवं हैंडपंप मैकेनिकों को बिंदुवार जानकारी दी गई। बैठक में एफटीकेके माध्यम से समस्त पेयजल स्त्रोतों के जल परीक्षण कर उसके परिणाम जिला कार्यालय भेजने के निर्देश भी दिए गए।

साथ ही उपखंड कार्यालय खिलचीपुर में ÷एक पेड़ मां के नाम÷ अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कर अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया।

कृषि वैज्ञानिकों की सलाह 4 इंच बारिश के बाद ही किसान करें बोवनी

जल्दी पकने वाली किस्मों के बीजों की दी जानकारी

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद खरीफ फसलों में पानी भरने, खरपतवार और कीड़े-मकोड़ों का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) शाजापुर ने किसानों के लिए एक जरूरी सलाह जारी की है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से अपील की है कि वे मौसम को देखकर ही खेतों में काम करें और फसलों की लगातार देखरेख करते रहें, ताकि नुकसान से बचा जा सके।

केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. एसएस धाकड़, डॉ. डी.के. तिवारी और डॉ. मुकेश सिंह ने सतगांव सप्टी, बाईहेड़ा और सुनेरा गांवों का दौरा कर किसानों को खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारियां दीं। वैज्ञानिकों ने कहा कि जिन किसानों ने अभी तक सोयाबीन नहीं बोया है, वे खेत में कम से कम 100 मिमी (करीब 4 इंच) बारिश होने के बाद ही बुवाई करें। (अभी जिले में करीब 9 इंच तक बारिश हो चुकी है।) अगर बुवाई में देरी हो रही है, तो जल्दी पकने वाली किस्मों के बीज ही चुनें। वहीं उड़द और मूंग की बुवाई 20 जुलाई तक की जा सकती है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि सोयाबीन की बुवाई के लिए शाजापुर जिले की जलवायु में जेएस-2069, जेएस-2098, आवीएस-2024 और एनआरसी-150 किस्में उपयुक्त मानी जाती हैं। इनमें अच्छी उत्पादन क्षमता, बेहतर अंकुरण और क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रदर्शन देखने को मिलता है। किसान केवल प्रमाणित और टैग लगे बीज ही खरीदें और बुवाई से पहले बीजोपचार अवश्य करें। खेत में पर्याप्त नमी होने पर ही बुवाई करें ताकि अंकुरण अच्छा हो। अधिक जानकारी और अपनी भूमि के अनुसार उपयुक्त किस्म के चयन के लिए स्थानीय कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह अवश्य लें। इससे बेहतर उत्पादन और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ती है।

बीज उपचार जरूरी, ऐसे बचाएं फसल- वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे केवल उन्हीं बीजों को बोएं जिनकी अंकुरण (उगने की) क्षमता कम से कम 70 फीसदी हो। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशी, कीटनाशी और जैव उर्वरकों (कल्चर) से अच्छी तरह साफ और उपचारित जरूर कर लें। अगर सोयाबीन के पौधे कम उगते हैं, तो खाली जगहों पर दोबारा बीज डालकर (गैप फिलिंग) पौधों की संख्या पूरी करें।

जल निकासी और कीड़ों से बचाव के उपाय- खेतों में पानी न भरे, इसके लिए पानी निकालने का सही इंतजाम करना बहुत जरूरी है। जब फसल 15 से 20 दिन की हो जाए, तो समय पर निंदाई-गुड़ाई करके खरपतवार को साफ कर लें। सोयाबीन में अगर किसी भी कीड़े या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो मनमर्जी से दवा न डालें, बल्कि केवल कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई दवाओं का ही छिड़काव करें। कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों से कहा है कि खेती में किसी भी तरह की समस्या आने पर वे तुरंत केंद्र या अपने पास के कृषि विभाग के दफ्तर से संपर्क कर सलाह ले सकते हैं।

करंट लगने से हुई मवेशी की मौत, मौके पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। बस स्टैंड परिसर में मंगलवार रात करंट फैलने से एक गोवंश की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर गौरक्षा सेना के पदाधिकारी और बिजली कंपनी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने विद्युत आपूर्ति में आई खराबी को दूर कर स्थिति को सुरक्षित किया।

गौरक्षा सेना के नगर महासचिव हर्षित परमार ने बताया कि उन्हें बस स्टैंड परिसर में एक नंदी के करंट की चपेट में आने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा और अन्य सदस्य भारी बारिश के बावजूद मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक गोवंश की मौत हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस स्टैंड परिसर में लगे लोहे के अर्थिंग में करंट प्रवाहित हो रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। गौरक्षा सेना ने तुरंत बिजली कंपनी को घटना की जानकारी दी। जब विवि कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और करंट के स्त्रोत की तलाश कर सुधार कार्य प्रारंभ किया। बिजली कंपनी के जेई रामप्रसाद अहिरवार ने बताया कि जांच में बस स्टैंड परिसर स्थित सम्राट लस्सी की दुकान की वायरिंग में खराबी पाई गई, जिसके कारण करंट फैल रहा था। इस खराबी को तत्काल ठीक कर दिया गया। इस घटना के बाद नगर पालिका की टीम ने मृत नंदी को मौके से हटवाकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान खुले विद्युत उपकरणों और संदिग्ध बिजली के तारों से दूरी बनाए रखें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।

रेवाबाग में अवैध शराब मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

तीन जुलाई को सात पेटी देशी शराब बरामद हुई थी, कार्रवाई के बाद फरार हुआ आरोपी आखिरकार आबकारी विभाग की गिरफ्त में आया

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अवैध शराब के संग्रहण और विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में रेवाबाग में सात पेटी देशी शराब बरामदगी मामले के फरार आरोपी को आबकारी विभाग ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, विक्रय और परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

आबकारी विभाग के अनुसार 3 जुलाई 2026 को वृत्त देवास (अ) की टीम ने मुखबिर की सूचना पर रेवाबाग स्थित कन्हैयालाल चौहान के बाड़े पर दबिश दी थी। कार्रवाई के दौरान वहां से चार पेटी देशी मसाला एवं तीन पेटी देशी प्लेन शराब सहित कुल 63 बल्क लीटर अवैध मदिरा बरामद की गई थी। मौके से आरोपी कन्हैयालाल चौहान फरार हो गया था। उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।

लगातार तलाश के बाद आबकारी टीम ने बुधवार को फरार आरोपी कन्हैयालाल चौहान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया, आरक्षक निहाल खत्री, दीपक तटवाड़े सहित आबकारी अमले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

वर्षा ऋतु में सर्पदंश से बचाव एवं सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। वर्षा ऋतु में खेतों, झाड़ियों, जलभराव वाले क्षेत्रों तथा आवासीय परिसरों में सांपों की गतिविधियां बढ़ने के कारण सर्पदंश की घटनाओं की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि सर्पदंश की स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि बिना समय गंवाए तत्काल निकटतम शासकीय अस्पताल पहुंचकर उपचार कराएं।

सीएमएचओ डॉ सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि जिले की सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में सर्पदंश के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों के साथ एंटी-स्नेक वेनम (एएसवी) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि समय पर सही उपचार मिलने से अधिकांश सर्पदंश पीड़ितों का सफल उपचार संभव है।

उन्होंने बताया कि सर्पदंश होने पर पीड़ित को शांत एवं स्थिर रखें तथा अनावश्यक चलने-फिरने से बचाएं। दंश वाले स्थान को साफ पानी से धोकर स्वच्छ कपड़े से ढक दें और जिस अंग पर सांप ने काटा हो उसे यथासंभव स्थिर रखें। सूजन की संभावना को देखते हुए अंगूठी, कड़ा, घड़ी, बेल्ट अथवा अन्य आभूषण निकाल दें। यदि पीड़ित बेहोश हो या उल्टी की संभावना हो तो उसे करवट की स्थिति में लिटाकर अस्पताल ले जाएं। यदि सुरक्षित रूप से संभव हो तो चिकित्सक को सर्पदंश का समय तथा सांप का स्वरूप बताएं, लेकिन सांप को पकड़ने या मारने का प्रयास बिल्कुल न करें।

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र अथवा किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का सहारा न लें। दंश वाले स्थान को काटने, चूसने या चीरा लगाने का प्रयास न करें तथा कसकर पट्टी न बांधें। बर्फ, तेल, मिट्टी, रसायन या किसी जड़ी-बूटी का उपयोग न करें और बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई दवा न लें। उपचार में देरी करना जानलेवा साबित हो सकता है।

नागरिकों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। खेतों, झाड़ियों अथवा अंधेरे स्थानों पर जाते समय पैरों को पूरी तरह ढकने वाले जूते पहनें, रात में हमेशा टॉर्च का उपयोग करें तथा हाथ या पैर किसी स्थान पर रखने से पहले वहां अच्छी तरह देख लें। फर्श पर सोने से बचें और आवश्यकता होने पर अच्छी तरह बंद मच्छरदानी का उपयोग करें। घर एवं आसपास साफ-सफाई बनाए रखें, झाड़ियां, कचरा एवं लकड़ियों के ढेर हटाएं तथा चूहों की संख्या नियंत्रित रखें, क्योंकि चूहे सांपों को आकर्षित करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार काटे गए स्थान पर तेज दर्द या सूजन, पलकों का भारी होना, धुंधला दिखाई देना, अत्यधिक पसीना आना, मतली या उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, कमजोरी अथवा बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेना आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि सर्पदंश की किसी भी घटना में घबराने के बजाय तुरंत शासकीय अस्पताल पहुंचें। समय पर उपचार मिलने से अधिकांश मामलों में रोगी का जीवन बचाया जा सकता है।

विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए 8 से 15 जुलाई तक महाविद्यालयों में लगेगा 'प्रवेश मेला'

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 8 से 15 जुलाई 2026 तक प्रवेश मेला आयोजित किया जा रहा है। अतिरिक्त सीएलसी राउंड के दौरान प्रवेश प्रक्रिया को गति देने एवं पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए यह विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

प्रवेश मेले के दौरान महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पंजीयन, चॉइस फिलिंग एवं संशोधन, दस्तावेज सत्यापन, सीट आवंटन संबंधी मार्गदर्शन तथा शुल्क भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पात्र विद्यार्थी उसी दिन अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। महाविद्यालयों में प्रवेश मेला प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा।

महाविद्यालयों द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध लंबित पंजीयन, सत्यापन, प्रवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद भी शुल्क जमा नहीं करने वाले विद्यार्थियों की सूची का परीक्षण कर उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाएगा। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें प्रवेश लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिन पाठ्यक्रमों एवं संकायों में रिक्त सीटों की संख्या अधिक है, वहां विशेष प्रयास किए जाएंगे। विद्यार्थियों को उपलब्ध पाठ्यक्रमों, विषय चयन एवं चॉइस संशोधन के संबंध में आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाएगा। साथ ही स्थानीय विद्यालयों, जनप्रतिनिधियों, पालकों एवं पूर्व विद्यार्थियों के सहयोग से प्रवेश जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

प्रत्येक महाविद्यालय में प्राचार्य की निगरानी में प्रतिदिन प्रवेश की समीक्षा की जाएगी तथा विभागवार एवं संकायवार लक्ष्य निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी। जिला नोडल अधिकारी अधिक रिक्त सीट वाले महाविद्यालयों की विशेष निगरानी करेंगे और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएंगे। समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि प्रवेश मेला केवल औपचारिक आयोजन न होकर अधिकतम प्रवेश, उसी दिन प्रवेश की कार्यपद्धति पर संचालित किया जाए।

एसडीएम मुरार ने किया अपने क्षेत्र की शराब दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण

ग्वालियर/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरार श्री नरेशचंद्र गुप्ता द्वारा गत रात्रि अनुभाग मुरार के अंतर्गत धर्मवीर पेट्रोल पंप के समीप स्थित वाइन शॉप एवं गोला का मंदिर चौराहे पर स्थित कंपोजिट वाइन शॉप का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित समय के पश्चात दुकानें खुली पाई जाने पर दोनों दुकानों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरार श्री नरेशचंद्र गुप्ता द्वारा अपने दल के साथ धर्मवीर पेट्रोल पंप के समीप स्थित वाइन शॉप का गत रात्रि 11.50 बजे निरीक्षण किया गया। वाइन शॉप बंद होने का निर्धारित समय रात्रि 11.30 बजे तक है। इसके बाद भी रात्रि 11.50 बजे तक दुकान खुली हुई थी और शराब का विक्रय किया जा रहा था। साथ ही गोला का मंदिर चौराहे पर भी रात्रि 11.40 बजे दुकान खुली होकर शराब का विक्रय होना पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री नरेशचंद्र गुप्ता ने अपने दल के साथ दोनों दुकानों का निरीक्षण कर पंचनामा भी बनवाया और दुकान संचालकों को समय पर दुकानें बंद करने की हिदायत दी।

अनुविभागीय अधिकारी श्री नरेशचंद्र गुप्ता ने दोनों दुकानों के निरीक्षण के दौरान तैयार किए गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने हेतु जिला आबकारी अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा है।

स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए वैल्यू एडेड कोर्स का चयन अनिवार्य

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वैल्यू एडेड कोर्स, संवैधानिक, मानवीय एवं नैतिक मूल्य तथा पर्यावरण शिक्षा एवं स्थिरता आधारित पाठ्यक्रमों का चयन अनिवार्य किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी करीकुलम एण्ड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम्स (सीसीएफपीजी), जून-2024 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के नवीन अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्नातकोत्तर विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में 2 क्रेडिट पॉइंट का एक वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम लेना होगा।

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विषय समूहों अंतर्गत पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें रोजगार एवं उद्यमिता कौशल, योग एवं ध्यान द्वारा तनाव प्रबंधन, पर्यावरण मनोविज्ञान, शोध लेखन कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, नवाचार एवं उद्यमिता जैसे विषय शामिल हैं।

इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल, नैतिक मूल्यों, नवाचार क्षमता एवं रोजगारपरक दक्षताओं से जोड़ना है। सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक आवश्यकता और विषय की उपयोगिता के अनुसार इन पाठ्यक्रमों के चयन में आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। इस पहल से स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल आधारित एवं मूल्यपरक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

मंडी में किसानों और व्यापारियों को मिलें बेहतर सुविधाएं - कलेक्टर

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने आष्टा सिविल अस्पताल एवं आष्टा की नवीन कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आष्टा सिविल अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, प्रसूति कक्ष, आपातकालीन सेवाओं, जांच सुविधाओं तथा साफ-सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता, दवाओं के स्टॉक तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने तथा शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीबीएमओ डॉ. अमित माथुर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी।

कलेक्टर श्री बालागुरू के. नवीन कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। कृषि उपज मंडी के कार्यालय अधीक्षक अरविंद झवर ने मंडी परिसर की व्यवस्थाओं से अवगत कराते हुए बताया कि मंडी में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की स्थायी व्यवस्था के साथ-साथ दुकानों का निर्माण शीघ्र कराया जाना आवश्यक है। इस पर कलेक्टर ने मंडी परिसर में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया तथा निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों, व्यापारिक सुविधाओं, किसानों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं, सड़क, शेड, पेयजल, विद्युत एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किए जाएं तथा निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने किसानों एवं व्यापारियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए मंडी परिसर में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को शीघ्र विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों तथा पेयजल व्यवस्था के लिए नगर पालिका के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आष्टा एसडीएम श्री महेंद्र प्रताप सिंह किरार, तहसीलदार श्री राम पगारे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

शासकीय हाई स्कूल दुधाना में 20 विद्यार्थियों को मिली साइकिल, वितरण समारोह आयोजित

सरपंच राकेश जयसवाल ने सभी छात्राओं को दी बधाई उज्जवल भविष्य के लिए की कामना

अकोदिया/ अमर सिंह मेवाडा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अकोदिया मोहन बड़ोदिया - शाजापुर जिले के दुधाना स्थित शासकीय हाई स्कूल में साइकिल वितरण समारोह का आयोजन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत दुधाना के युवा सरपंच राकेश जायसवाल सहित अनेक अतिथि शामिल हुए।

समारोह के दौरान विद्यालय के 20 विद्यार्थियों को शासन की योजना के तहत निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं। साइकिल मिलने से छात्र-छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस योजना का उद्देश्य दूरदराज से आने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा प्रदान करना है।

कार्यक्रम में पंचायत सचिव कैलाश कटारिया, संकुल प्राचार्य आशा श्रीवास्तव, श्याम कारपेंटर, मानसिंह भीलाला, रोजगार सहायक ओमप्रकाश बैरागी, महेश विश्वकर्मा और राकेश पुष्पद सहित विद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने, मन लगाकर पढ़ाई करने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम मे अतिथि के रूप में मौजूद सरपंच राकेश जायसवाल ने हाई सेकेंडरी स्कूल के सभी छात्र छात्राओं से मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करने की बात करते हुए उन्हें साइकिल का वितरण किया 20 विद्यार्थियों को साइकिल का वितरण कर उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की सरपंच श्री जायसवाल ने कहा कि इस दुनिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है पढ़ाई लिखाई क्योंकि जिस घर में घर के बालक बालिकाएं बचपन से ही अगर पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो वह एक दिन अवश्य अपने माता-पिता गांव व क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे की बात कही।

प्रभात बर्वे का निधन पत्रकारिता एवं सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति : यात्री विकास एवं सुझाव मंच

नागदा/ राजेश सकलेचा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर के वरिष्ठ, मिलनसार एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े सक्रिय व्यक्तित्व प्रभात बर्वे का मंगलवार को हृदयाघात से आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही नगर के सामाजिक, पत्रकारिता एवं विभिन्न संगठनों में शोक की लहर व्याप्त हो गई।

यात्री विकास एवं सुझाव मंच के संस्थापक राजेश सकलेचा, अध्यक्ष नितिन जैन (उन्हेल), सचिव रवि चौहान, कोषाध्यक्ष दीपक जैन, परामर्शदाता कैलाश सनोलिया, पंकज मारू, के. के. साहू, संयोजक चेतन यादव, सुनील त्रिवेदी, भवानी सिंह देवड़ा सहित मंच के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने प्रभात बर्वे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया।

मंच ने जारी शोक संदेश में कहा कि प्रभात बर्वे लंबे समय से समाचार एवं जनसंपर्क के क्षेत्र में सक्रिय रहकर सामाजिक, धार्मिक एवं जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता से समाचारों के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों एवं मीडिया संस्थानों तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते रहे। उनकी निष्पक्ष कार्यशैली, सामाजिक प्रतिबद्धता, सकारात्मक सोच एवं सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व ने उन्हें समाज में विशिष्ट पहचान दिलाई।

एव नागदा जर्नालिस्ट क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भी प्रभात बर्वे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका असामयिक निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। समाज एवं पत्रकारिता के प्रति उनकी सेवाओं को सदैव स्मरण किया जाएगा।

यात्री विकास एवं सुझाव मंच ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिजनों को इस दुःख की घड़ी में संबल एवं धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की।

धार जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही, कुक्षी वृत्त में 69,168 मूल्य की विदेशी शराब जब्त

धार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के निर्देशानुसार तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्री दीपक अवस्थी के मार्गदर्शन में धार जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में आबकारी वृत्त कुक्षी द्वारा ग्राम नरझली में एक बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में अवैध विदेशी मदिरा जब्त की गई है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री मोहनलाल भायल के नेतृत्व में वृत्त कुक्षी की आबकारी उप निरीक्षक सुश्री रीनू भिंडे द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना पर ग्राम नरझली स्थित एक मकान की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वहां से 15 पेटी विभिन्न ब्रांड की विदेशी मदिरा बरामद हुई।

कार्यवाही में कुल 167.28 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जब्त की गई, जिसका अनुमानित मूल्य 69,168 रुपये है। जब्त सामग्री में 144 नग माउंट सुपर स्ट्रांग बीयर (500ml), 05 पेटी लेमाउंट बीयर (कुल 120 नग, 500ml), 02 पेटी लंदन प्राइड व्हिस्की (24 बोतल, 750ml) और 02 पेटी बैगपाइपर व्हिस्की (96 पाव, 180ml) शामिल हैं।मौके पर आरोपी लोकेश पिता गणपत डोडवे, निवासी नरझली, फरार होने में सफल रहा। विभाग द्वारा उक्त आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें : अपर कलेक्टर

बरसात में पुल-पुलियों पर पानी होने पर स्कूली वाहन न निकालें

आलोट/ राकेश चौहान/ दैनिक मालवा हेराल्ड। स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर सभागार में जिले के स्कूल संचालकों एवं बस ऑपरेटरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र रावत, सीएसपी, जिला परिवहन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, डीसी होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी स्कूली वाहनों के दस्तावेज, फिटनेस, बीमा, परमिट, पीयूसी एवं अन्य आवश्यक अभिलेख अद्यतन रहें। बस चालक एवं परिचालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा पुलिस सत्यापन होना अनिवार्य है। बसों में स्पीड गवर्नर, इमरजेंसी विंडो, पैनिक बटन, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे सहित सभी सुरक्षा उपकरण कार्यशील अवस्था में रहें।

निर्देश दिए गए कि बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जाए तथा बच्चों को चालक के केबिन में न बैठाया जाए। बसों पर शिकायत नंबर, स्कूल बस का स्पष्ट उल्लेख एवं आवश्यक रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाएं। चालक एवं परिचालक निर्धारित वर्दी व नेम प्लेट पहनें तथा निर्धारित गति सीमा का पालन करें।

बैठक में विशेष रूप से वर्षा ऋतु के दौरान पुल-पुलियों अथवा रपटों पर पानी होने की स्थिति में किसी भी स्कूली वाहन को पार नहीं कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने सभी स्कूल संचालकों एवं बस ऑपरेटरों से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र 30 जुलाई तक आमंत्रित

रीवा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्राचार्य शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रीवा संभाग रीवा ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य सिविल सेवा परीक्षा/ बैंकिंग/ रेलवे/ एसएससी/ बीमा एवं मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रीवा में निःशुल्क प्रशिक्षण 20 अगस्त 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक निर्धारित प्रपत्र में अपने आवेदन पत्र 30 जुलाई 2026 तक स्वयं अथवा रजिस्टर्ड डाक से या कार्यालय समय में जमा कर सकते हैं। प्रशिक्षण हेतु प्रवेश की शर्तों के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। आवेदक की आयु आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक न हो। आवेदक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो।

आवेदक की न्यूतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण हेतु चयन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के घटते क्रम में मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा। आवेदक पूर्व में किसी परीक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण का लाभ न लिया हो। प्रशिक्षण केन्द्र के लिए केन्द्र में उपस्थित होने पर चयनित प्रशिक्षणार्थी को पाँच सौ रुपए कॉशन मनी के रूप में तथा अनुबंध जमा पर ही प्रवेश दिया जाएगा। काशन मनी राशि प्रशिक्षण के पश्चात आवेदन करने पर लौटाई जाएगी।

एटीएफसी आदित्य टेक्नो द्वारा रेलवे क्षेत्र से जुड़कर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण किया जाना मध्यप्रदेश के लिए गौरव : मुख्यमंत्री

धार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर-3 स्थित एटीएफसी आदित्य टेक्नो फेब प्राइवेट लिमिटेड की द्वितीय विनिर्माण इकाई का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कंपनी परिसर का अवलोकन किया तथा आधुनिक मशीनों एवं उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी कंपनी के पदाधिकारियों से प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने नई इकाई के शुभारंभ पर कंपनी प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए इसे प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

इस अवसर पर धार विधायक श्रीमती नीना वर्मा, स्थानीय जनप्रतिनिधि श्री नीलेश भारती, श्री श्रवण चावड़ा, कंपनी के चेयरमैन श्री सुनेर सिंह छड़ोदी, डायरेक्टर श्री धीरेन्द्र छड़ोदी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री लक्ष्मीनारायण छड़ोदी, ज्वाइंट डायरेक्टर श्री राजेश राजपूत, श्री अतुल जैन, श्री विक्रांत पटेल, श्री पी.डी. शर्मा, इंदौर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, पुलिस महानिरीक्षक श्री अनुराग तथा कलेक्टर धार श्री राजीव रंजन मीना सहित उद्योग जगत के अनेक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेलवे अधोसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण का कार्य अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए आधुनिक तकनीक और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि पीथमपुर का औद्योगिक क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में अपनी पहचान बना चुका है। यहां स्थापित उद्योग न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहे हैं, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित कर रहे हैं। एटीएफसी आदित्य टेक्नो फेब प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रेलवे क्षेत्र से जुड़कर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण किया जाना मालवा अंचल के साथ-साथ पूरे मध्यप्रदेश के लिए गौरव की बात है।मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। निवेश, नवाचार और आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहन देने के साथ उद्योगों को आवश्यक अधोसंरचना एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मध्यप्रदेश देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनकर उभर रहा है।

मुकेश होती पुन बने नगर कांग्रेस अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में उत्साह

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बदनावर नगर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर एक बार फिर युवा कांग्रेस नेता मुकेश होती की नियुक्ति कर संगठन में निरंतरता बनाए रखने का निर्णय लिया है। यह नियुक्ति मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी महासचिव डॉ. संजय कामले के हस्ताक्षरयुक्त अधिकृत पत्र के माध्यम से जारी की गई है।

होती पिछले लगभग दो वर्षों से नगर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। उनके कार्यकाल में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने तथा विभिन्न जनहित और संगठनात्मक कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन पर पुनः विश्वास जताते हुए उन्हें इसी दायित्व पर यथावत नियुक्त किया है।

नगर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने होती को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में नगर कांग्रेस संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा पार्टी की नीतियों को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य किया जाएगा।

होती ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं प्रदेश कांग्रेस संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने और आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के लिए वे लगातार प्रयासरत रहेंगे। आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क अभियानों को लेकर भी जल्द ही नगर स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा, ताकि संगठन को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाया जा सके।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला संपन्न स्वच्छता से समझौता नहीं, अब लापरवाही पर होगी सीधे चालानी कार्यवाही - महापौर

जबलपुर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रावधानों की जानकारी देने तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज बुधवार को घंटाघर स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस कल्चरल एंड इंफर्मेशन सेंटर में जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों एवं अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह ÷अन्नू÷ ने कहा कि संपूर्ण स्वच्छता पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है, अब शहर की स्वच्छता और नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।

कार्यशाला में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। कार्यशाला में नगर निगम अध्यक्ष श्री रिकुंज विज, सभी नगर परिषदों के अध्यक्ष, नगर निगम के एमआईसी सदस्य, सभी पार्षद, कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार, नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

महापौर ने कहा कि हम सबके ऊपर अब पहले से कहीं अधिक दायित्व बढ़ गया है। जबलपुर को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नए नियम शहर को कचरा मुक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। स्वच्छता को लेकर लापरवाही बरतने वालों, सड़कों पर कचरा फेंकने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई को अब कानूनी रूप दे दिया गया है। महापौर ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वार्ड स्तर पर विशेष समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां सीधे जनता से जुड़कर जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करेंगी। उन्होंने कहा कि शहर से निकलने वाले ठोस कचरे के सही निष्पादन के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है।

राशि गबन के मामलों में पूर्व सरपंच, पूर्व सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ जेल वारंट जारी

रीवा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में पंचायती राज व्यवस्था के तहत विकास कार्यों की राशि में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा मेहताब सिंह गुर्जर द्वारा भ्रष्टाचार और शासकीय राशि के गबन के अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए एक पूर्व सरपंच, एक पूर्व सचिव और एक ग्राम रोजगार सहायक के खिलाफ गिरफ्तारी और जेल भेजने संबंधी वारंट जारी किए हैं। यह कड़ा कदम मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के तहत उठाया गया है। सीईओ जिला पंचायत द्वारा जारी वारंट के अनुसार जनपद पंचायत त्योथर की ग्राम पंचायत फरहदी में खेत तालाब निर्माण और मेंढ़ बंधान निर्माण कार्यों में कुल 1,00,237 रुपये की राशि का गबन किया गया था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव राजबहोर यादव और ग्राम रोजगार सहायक नारायण प्रसाद मिश्रा को जिम्मेदार पाया गया। जिला पंचायत कार्यालय द्वारा नवंबर 2025 से जून 2026 के बीच कई बार लिखित नोटिस जारी कर वसूली राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे।

शहीद राठौर की 25 वी पुण्यतिथि रजत जयंती के रूप में आज पाना में मनाएँगे

जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक व मीडिया कर्मी देंगे श्रद्धांजलि

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अमर शहीद नायब सूबेदार रविंद्र सिंह राठौर की 25 वी पुण्यतिथि गुरुवार को आज उनके पेत्रक गांव पाना में प्रातः 9:30 बजे मनाई जाएगी। बलिदानी राठौर की की शहादत को शहीद रविंद्र सिंह राठौर स्मृति संस्था के बैनर तले स्मारक स्थल एवं प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। गुरुवार को प्रातः साढ़े 9 बजे बलिदानी राठौर की धर्मपत्नी प्रताप कुंवर राठौर परिजन सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, राजस्व विभाग सहित विभिन्न संगठन के पदाधिकारी व राष्ट्रभक्त उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे गौरतलब है कि शहीद रविंद्र सिंह राठौर 9 जुलाई 2001 को जम्मू कश्मीर के सुरनकोट तहसील के जंगलों में सेना के विशेष अभियान ऑपरेशन रक्षक का नेतृत्व करते हुए आर्तकियों का मुकाबला करते हुए तीन आर्तकियों को मार गिरा कर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बलिदानी राठौर का जन्म बदनावर तहसील के अंतिम छोर पर बसे छोटे से गांव पाना में नाथू सिंह राठौर के यहां हुआ था। रविंद्र सिंह राठौर बचपन से ही देश सेवा के प्रति उत्सुक रहे एवं सेवा में भर्ती होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। आप 1 जनवरी 1979 को पेरा रेजीमेंट में चयनित होकर बैंगलोर से प्रशिक्षण प्राप्त कर आगरा में पदस्थ हुए। आप सेना में सिपाही , लांस नायक, नायक, हवलदार सूबेदार एवं नायब सूबेदार के पद पर सेवारत रहे। आपके अदम्य साहस को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा बल एनएसजी कमांडो में 8 वर्ष सेवा का अवसर मिला। आप देश सेवा करते हुए 9 जुलाई 2001 को शहीद हो गए थे तब से पेत्रक गांव पाना में प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर स्मृति संस्था द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है एवं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। कानवन मांगोद टूलाइन मार्ग स्थित पाना फांटे पर प्रस्तावित शहीद वाटिका में पौधरोपण भी किया जाएगा।

कार्यालय नगर पालिक निगम, देवास (म.प्र)

// निविदा सूचना //

सूचना क्रं./80/लो.नि.वि./26 — देवास, दिनांक 06.07.2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयाविधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2026_UAD_519510_1	वार्ड क्रं. 21 मे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रिपेयर कार्य।	60 दिवस 6,50,000/-	2,000/- 6,500/-	20/07/2026
2	2026_UAD_519475_1	वार्ड क्रं. 37 शालिनी रोड़ स्थित गणेश मंदिर वाली गली में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	60 दिवस 5,00,000/-	2,000/- 5,000/-	20/07/2026
3	2026_UAD_519532_1	वार्ड क्रं. 40 शांतिपुरा गार्डन मे ओटला, टीन शेड, ए.सी. पी. गेट निर्माण एवं जीम उपकरण प्रदाय कर फिक्सिंग करने का कार्य। (चतुर्थ निविदा)	45 दिवस 4,90,000/-	2,000/- 4,900/-	20/07/2026
4	2026_UAD_519532_1	वार्ड क्रं. 41 कटी घाटी वाली गली, खरी बावड़ी वाली गली एवं अन्य गलियों मे सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।	60 दिवस 9,98,000/-	2,000/- 9,980/-	20/07/2026
5	2026_UAD_519532_1	वार्ड क्रं. 08 प्रभुश्री नारायण नगर स्थित गार्डन की बाउण्ड्रीवाल एवं पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य।	60 दिवस 15,00,000/-	2,000/- 11,250/-	05/08/2026
6	2026_UAD_519532_1	वार्ड क्रं.20 रामनगर एनेक्स गार्डन की बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं पेवर्स ब्लाक लगाने का कार्य।	60 दिवस 18,00,000/-	2,000/- 13,500/-	05/08/2026
7	2026_UAD_519532_1	वार्ड क्रं. 25 सिविल लाईन रोड़ पर डॉ. मुंगी जी के एवं पारसमल जैन जी के मकान के पास रिफ. पेवर्स ब्लाक लगाने का कार्य।	60 दिवस 14,50,000/-	2,000/- 10,875/-	05/08/2026
8	2026_UAD_519532_1	वार्ड क्रं. 31 अम्बेडकर नगर मे सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।	60 दिवस 14,47,000/-	2,000/- 10,853/-	05/08/2026

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम देवास (म.प्र)

विद्यालयों के निरीक्षण में कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, लापरवाही पर जताई नाराजगी

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने बुधवार को जिले के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था, अधोसंरचना एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के प्रति नाराजगी व्यक्त की।

कलेक्टर ने सर्वप्रथम प्राथमिक शाला आम्बा का निरीक्षण किया तथा विद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों एवं व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इसके पश्चात उन्होंने एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय आम्बा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध नहीं कराए जाने पर उन्होंने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित लव-कुश स्वयं सहायता समूह को नोटिस देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री बच्चूसिंह सिंगाड की कार्यप्रणाली की सराहना की। उन्होंने विद्यालय में एकमात्र शिक्षक होने के बावजूद विद्यालय की व्यवस्थाओं का प्रभावी संचालन एवं विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने पर उनकी प्रशंसा करते हुए इसी प्रकार समर्पित भाव से कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

इसके उपरांत कलेक्टर ने विकासखंड रामा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय हिड़ी बड़ी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा निर्धारित समय से पूर्व दोपहर 2ः30 बजे ही विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी गई थी। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नोटिस देने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यालय निर्धारित समय तक संचालित किए जाएं तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

कलेक्टर ने एकीकृत शासकीय नवीन माध्यमिक विद्यालय गोमला का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय भवन की मरम्मत कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय के बरामदे में खड़ा ट्रैक्टर तत्काल हटाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं विद्यालय परिसर का सुव्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित अध्ययन-अध्यापन, समय पर मध्यान्ह भोजन, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरीक्षण के दौरान दिए गए सभी निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कोटवार बनेंगे आपदा सुरक्षा के प्रहरीः शमशाबाद में आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण आयोजित

विदिशा/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार एवं जिला होमगार्ड सेनानी श्री मयंक कुमार जैन के मार्गदर्शन में बुधवार को तहसील कार्यालय शमशाबाद में कोटवारों के लिए आपदा प्रबंधन विषयक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम स्तर पर कार्यरत कोटवारों को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं आकस्मिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना तथा उन्हें ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम बनाना था।

प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने बाढ़ की स्थिति में सुरक्षित बचाव एवं राहत कार्यों, सर्पदंश होने पर तत्काल किए जाने वाले प्राथमिक उपचार, अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय, आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानियों तथा फर्स्ट एड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से दीं। प्रशिक्षण में बताया गया कि आपदा के समय घबराने के बजाय सही जानकारी और त्वरित कार्रवाई से जनहानि एवं संपत्ति के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी कोटवारों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने ग्रामों में पहुंचकर ग्रामीणों को आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करें। साथ ही स्थानीय स्तर पर जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर लोगों को समय रहते सतर्क करने तथा किसी भी आपदा की सूचना तत्काल प्रशासन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

प्रशिक्षण में विदिशा से पहुंची एसडीआरएफ टीम ने व्यावहारिक एवं तकनीकी जानकारी भी साझा की। टीम के प्रभारी एएसआई लक्ष्मी विश्वकर्मा के नेतृत्व में सैनिक संदीप, श्री देवेंद्र कटोरिया श्री संजय ने विभिन्न आपदाओं के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा तकनीकों, बचाव के तरीकों और प्राथमिक उपचार की जानकारी देकर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

पठारी खेल मैदान निर्माण प्रकरणः स्वर्गीय कार्यपालन यंत्री अंबालाल उईके की निलंबन अवधि कर्तव्य अवधि घोषित

विदिशा/दैनिक मालवा हेराल्ड। विदिशा जिले के कुरवाई विकासखंड की ग्राम पठारी में स्टेडियम एवं खेल मैदान निर्माण कार्य में सामने आई अनियमितताओं से जुड़े प्रकरण में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। शासन ने स्वर्गीय तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री अंबालाल उईके की 18 जनवरी 2021 से 11 अप्रैल 2022 तक की निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि (ड्यूटी पीरियड) के रूप में मान्य कर दिया है।

प्रकरण के अनुसार प्रारंभिक जांच में पाया गया था कि खेल मैदान निर्माण के लिए चयनित स्थल योजना के मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं था। स्थल पहाड़ी एवं चट्टानी होने के कारण खेल गतिविधियों के संचालन के लिए अनुपयोगी पाया गया। इसके बावजूद योजना की संपूर्ण राशि व्यय कर कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया था। इन तथ्यों के आधार पर तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री अंबालाल उईके को 18 जनवरी 2021 को निलंबित किया गया तथा उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-14 के तहत विभागीय जांच प्रारंभ की गई।

विभाग द्वारा 17 मार्च 2021 को आरोप-पत्र जारी कर उनका प्रतिवाद मांगा गया। प्रतिवाद संतोषजनक नहीं पाए जाने पर जांच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति कर विस्तृत विभागीय जांच शुरू की गई। हालांकि जांच प्रक्रिया के दौरान तथा निलंबन अवधि में ही 11 अप्रैल 2022 को श्री उईके का निधन हो गया।

इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के 20 मई 2009 के परिपत्र के निर्देशों के अनुरूप सक्षम स्तर से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर 13 सितंबर 2024 को उनके विरुद्ध चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही बिना किसी दंड के समाप्त कर दी गई। हालांकि उस समय उनकी निलंबन अवधि के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।

अब राज्य शासन ने मूलभूत नियम 54-बी के तहत आदेश जारी करते हुए स्वर्गीय श्री अंबालाल उईके की 18 जनवरी 2021 से 11 अप्रैल 2022 तक की निलंबन अवधि को सभी प्रशासनिक एवं सेवा संबंधी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में दिए गए जीवन निर्वाह भत्ते की राशि का नियमानुसार समायोजन किया जाएगा।

इस निर्णय के साथ स्वर्गीय अधिकारी की लंबित सेवा संबंधी प्रक्रिया का औपचारिक निराकरण कर दिया गया है।

कलेक्टर ने विद्यालयों एवं स्वास्थ्य संस्थान का किया औचक निरीक्षण

अनुपस्थित शिक्षक पर नाराजगी, जर्जर भवन हटाने, स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने के दिए निर्देश

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने जिले के विभिन्न शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की उपस्थिति, आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता एवं मध्याह्न भोजन व्यवस्था का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण की शुरुआत उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय खरडू छोटी से हुई। विद्यालय में शिक्षक श्री मोहम्मद शाह अनुपस्थित पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि विद्यालय भवन जर्जर होने के कारण विद्यार्थियों को भवन के बाहर बैठाकर अध्ययन कराया जा रहा है। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जर्जर भवन को डिस्मेंटल (ध्वस्त) करने की आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इसके पश्चात कलेक्टर ने शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय खरडू बड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से संवाद किया तथा बच्चों से पाठ्यपुस्तक का वाचन करवाकर उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन किया। उन्होंने शिक्षकों को विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने इसके बाद पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पारा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर एवं आसपास गंदगी पाए जाने पर उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल साफ-सफाई कराने तथा विद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए।

दौरे के दौरान कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पारा का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं एवं संस्थान की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए, ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

इसके उपरांत कलेक्टर एकीकृत शासकीय नवीन माध्यमिक विद्यालय झुमका पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन ग्रहण किया तथा भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं होने पर समूह को नोटिस देने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय में रसोईघर (किचन) के अभाव को देखते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच को शीघ्र किचन निर्माण कराने के निर्देश दिए, जिससे मध्याह्न भोजन व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से संचालित हो सके।

निरीक्षण के अंतिम चरण में कलेक्टर ने एकीकृत शासकीय हाई स्कूल पिथनपुर का निरीक्षण कर विद्यालय की शैक्षणिक एवं आधारभूत व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी विद्यालयों के शिक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, विद्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय संस्थानों का नियमित निरीक्षण निरंतर जारी रहेगा तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बनी आत्मनिर्भरता का आधार

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना छोटे एवं रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों के लिए आर्थिक संबल बनकर उभरी है। इस योजना के माध्यम से अनेक छोटे व्यवसायियों को बिना किसी बड़ी औपचारिकता के कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। झाबुआ जिले की नगर परिषद थांदला निवासी श्रीमती पारी की सफलता की कहानी इसी का प्रेरणादायी उदाहरण है।

श्रीमती पारी वर्षों से सड़क किनारे ठेले पर फल एवं सब्जियों का विक्रय कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही थीं। सीमित पूंजी के कारण वे अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पा रही थीं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने से आवश्यक ऋण प्राप्त करना भी उनके लिए आसान नहीं था, जिससे आय बढ़ाने के प्रयास लगातार बाधित हो रहे थे।

इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने नगर परिषद थांदला के माध्यम से योजना में आवेदन किया। आवेदन स्वीकृत होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक, थांदला द्वारा उन्हें योजना के तहत 10,000 का प्रथम कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया गया। इस राशि से उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी तथा ठेले पर अधिक मात्रा और विविधता के साथ फल एवं सब्जियां रखना प्रारंभ किया।

व्यवसाय में सुधार और ग्राहकों की संख्या बढ़ने से उनकी आय में लगातार वृद्धि हुई। उन्होंने योजना के तहत प्राप्त प्रथम ऋण की सभी किस्तों का समय पर भुगतान किया। समय पर ऋण चुकाने के कारण उन्हें योजना के अगले चरण में ?20,000 का ऋण प्राप्त हुआ। इस राशि से उन्होंने अपने व्यवसाय का और अधिक विस्तार किया तथा आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके बाद ?20,000 का ऋण भी समय पर पूर्ण रूप से जमा करने पर अब उन्हें योजना के अंतर्गत ?50,000 तक का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिला है।

श्रीमती पारी बताती हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने उनके जीवन में आर्थिक आत्मविश्वास का संचार किया है। आज वे न केवल अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उनका कहना है कि यह योजना छोटे व्यवसायियों के लिए एक नई शुरुआत और आत्मनिर्भर बनने का सशक्त माध्यम है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से झाबुआ जिले में भी अनेक रेहड़ी-पटरी एवं फुटपाथ व्यवसायियों को स्वरोजगार को मजबूत करने का अवसर मिला है। यह योजना छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें सम्मानपूर्वक आजीविका अर्जित करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

कलेक्टर ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं ग्राम पंचायत सेमलिया बड़ा का किया निरीक्षण

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने बुधवार को ग्राम सेमलिया बड़ा पहुंचकर शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) एवं ग्राम पंचायत का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार तथा शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, सेमलिया बड़ा में कक्षाओं का अवलोकन किया तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षकों को विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं रुचिकर तरीके से अध्ययन कराने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों में निरंतर सुधार हो सके। कलेक्टर ने शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के उपस्थिति रजिस्टर का भी अवलोकन कर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कक्षा में विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई का स्तर जाना तथा स्वयं भी विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाकर उन्हें मन लगाकर अध्ययन करने और नियमित विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया।

इसके पश्चात कलेक्टर ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केन्द्र), सेमलिया बड़ा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आवश्यक व्यवस्थाओं एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आमजन को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सेमलिया बड़ा का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत में संचालित विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त की तथा पंचायत स्तर पर अभिलेखों एवं व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए सभी कार्यों को पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ संपादित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे, यह सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

पशुपालकों की बदहाल स्थिति पर सरकार तत्काल ठोस कदम उठाएं किसान नेता श्यामलाल जोकचंद

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। किसान नेता श्यामलाल जोकचंद ने प्रदेश और देश के पशुपालकों की लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए सरकार से तत्काल ठोस राहत पैकेज और प्रभावी नीतिगत निर्णय लेने की मांग की है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा कि बढ़ती लागत, पशु आहार की महंगाई, दूध के कम दाम, महंगा इलाज और सरकारी उपेक्षा के कारण पशुपालक वर्ग अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। यदि समय रहते सरकार ने संवेदनशील और ठोस कदम नहीं उठाए, तो पशुपालन का पारंपरिक व्यवसाय गहरे संकट में पहुंच जाएगा, जिसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

जोकचंद ने कहा कि सूखा भूसा, हरा चारा, पशु आहार (बाटा), खली, चूरी सहित अन्य आवश्यक सामग्री के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि दूध का मूल्य उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं बढ़ा है। इससे पशुपालकों को प्रतिदिन आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक पंजीकृत पशुपालक को प्रति पशु प्रतिमाह 60 किलोग्राम पशु आहार मात्र 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाए। साथ ही हरे एवं सूखे चारे की पर्याप्त व्यवस्था की जाए तथा पशुओं के लिए 100 प्रतिशत अनुदान पर आधुनिक एवं सुरक्षित शेड निर्माण योजना लागू की जाए। शासकीय पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सकों की नियुक्ति, आधुनिक उपकरणों और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए पशुओं का संपूर्ण उपचार निःशुल्क किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि स्वस्थ पशु ही समृद्ध पशुपालक और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। किसान नेता ने निजी बैंक और वित्तीय कंपनियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऊंची ब्याज दरों पर छोटे-छोटे ऋण देकर किसानों और पशुपालकों को कर्ज के जाल में फंसाया जा रहा है। मामूली चूक पर उनकी सिबिल खराब कर दी जाती है, जिससे वे भविष्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी ऋण लेने से वंचित हो जाते हैं। उन्होंने सरकार से बिना सिबिल की बाध्यता, सरल प्रक्रिया, न्यूनतम ब्याज दर और आसान मासिक किस्तों पर विशेष पशुपालन ऋण योजना लागू करने की मांग की। जोकचंद ने कहा कि पशुओं की खरीदी-बिक्री और परिवहन के दौरान वैध व्यापार करने वाले पशुपालकों को कई स्थानों पर अवैध वसूली, अनावश्यक रोक-टोक, गुंडागर्दी और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ऐसी अराजक प्रवृत्तियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई कर पशुपालकों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने बाजार में नकली दूध, नकली घी, नकली पनीर, नकली मक्खन और अन्य मिलावटी दुग्ध उत्पादों के बढ़ते कारोबार पर भी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि यह न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि ईमानदार पशुपालकों और डेयरी उत्पादकों के हितों पर भी सीधा प्रहार है।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निराकरण करें अधिकारी

खण्डवा/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करें। उन्होंने कहा कि संबंधित शिकायतकर्ता से बात करें, संबंधित शिकायत के बारे में जानकारी लें और शिकायत का संतुष्टि पूर्ण ढंग से निराकरण किया जाए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. नागार्जुन गौड़ा और अपर कलेक्टर श्री के आर बडोले सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने लीड बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि 30 जुलाई तक बैंक सखियों का चयन और प्रशिक्षण कराएं। उन्होंने कहा कि गांव की स्थानीय महिलाओं को ÷बैंक सखी÷ के रूप में चयनित कर गांव में नियुक्त कर ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा का लाभ दिलाएं। बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिला आपूर्ति अधिकारी से जिले में पेट्रोल एवं गैस की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि घरेलू सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी अधिकारियों से कहा कि ए आई का 30 दिन का कोर्स पूरा करें। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि जिन डॉक्टरों की ई-संजीवनी में ड्यूटी लगी है, और वे यदि ड्यूटी समय में ऑनलाइन नहीं रहते है, ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए खसरा नकल, फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी एवं नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि ई-ऑफिस का उपयोग करें एवं सभी सरकारी फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से ही भेजें।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने नगर निगम आयुक्त को पार्वती बाई धर्मशाला के पास वाली नाली एवं नालों की साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए । बैठक में उन्होंने मनरेगा योजना के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और केंद्रीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियो को निर्देश दिए कि संबल योजना के लंबित आवेदनों का सत्यापन करें। उन्होंने संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता की राशि के लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश भी दिए।

स्वास्थ्य केन्द्रों के निरीक्षण में व्यवस्थाओं की जांच, अनुपस्थिति एवं बंद पाए जाने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने बुधवार को जिले के स्वास्थ्य संस्थानों का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने उप स्वास्थ्य केन्द्र कालीदेवी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जानकारी मिली कि केन्द्र पर पिछले छह माह से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) पदस्थ नहीं है। साथ ही निरीक्षण के समय पदस्थ एएनएम भी अनुपस्थित पाई गई। इस पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र पर नियमित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके पश्चात कलेक्टर ने उप स्वास्थ्य केन्द्र पिथनपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद पाया गया। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं स्वास्थ्य संस्थान का नियमित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है तथा इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में निर्धारित समय पर स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति, नियमित सेवाएं तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो सकें।

मालिक, प्रकाशक, मुद्रक विजय शर्मा द्वारा 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं भगवती ऑफसेट 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक - विजय शर्मा, मो.नं. 94250-22499, फोन 0734-2553435 प्रधान संपादक : शुभम ताम्रकार (सभी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)

महाकाल क्षेत्र में फायर अफसर को थप्पड़ मारे

होटल संचालक के बेटे की दबंगई कैमरे में कैद- वायरलेस सेट और दस्तावेज फेंके, सरकारी काम में बाधा सहित चार धाराओं में केस, आरोपी फरार

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। महाकाल मंदिर क्षेत्र में फायर सेफ्टी जांच के दौरान नगर निगम के प्रभारी फायर अधिकारी के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच करने पहुंची निगम की टीम के सामने होटल संचालक के बेटे ने कथित तौर पर प्रभारी फायर अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद साहू को एक के बाद एक चार थप्पड़ जड़ दिए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे शहर में इसकी चर्चा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित चार धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

हाल ही में शहर में हुई आगजनी की घटनाओं के बाद नगर निगम महाकाल मंदिर क्षेत्र के होटल, लॉज और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी जांच अभियान चला रहा है। इसी क्रम में बुधवार को प्रभारी फायर अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद साहू अपनी टीम के साथ जयसिंहपुरा स्थित मां पीताम्बरा होटल रेजिडेंसी पहुंचे थे। टीम होटल प्रबंधन से फायर एनओसी, फायर ऑडिट रिपोर्ट और भवन अनुमति से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही थी।

प्रभारी फायर अधिकारी के अनुसार, उनके साथ आए कर्मचारी आशीष भाटी पुलिस बल लेने महाकाल थाने गए थे। इसी दौरान होटल संचालक मनोहरलाल अरोन्या का पुत्र विकास अरोन्या वहां पहुंचा और जांच का विरोध करते हुए विवाद करने लगा। आरोप है कि उसने अधिकारी का परिचय पत्र खींच लिया, रिसेप्शन पर रखा वायरलेस सेट, कार्बन पेपर और अन्य दस्तावेज बाहर फेंक दिए, जिससे वायरलेस सेट क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद उसने प्रभारी फायर अधिकारी को लगातार चार थप्पड़ मारे। इस हमले में अधिकारी के चेहरे, सिर और बाईं आंख में चोट आई। घटना के बाद फायर अधिकारी ने नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और महाकाल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, मारपीट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि आरोपी विकास अरोन्या घटना के बाद से फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

नकली नोट गिरोह में शामिल फरार आरोपी में किया सरेंडर

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर-उज्जैन के बीच नकली नोट छापने और खपाने के मामले का खुलासा दिसंबर में पुलिस ने किया था। 2 आरोपियों से 17.50 लाख के नकली नोट बरामद किये गये थे। मामले में गिरोह का सरगना और उसका साथी फरार थे। मंगलवार को एक फरार आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसे 5 दिनों की रिमांड पर लिया गया है।

दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में राज रॉयल कालोनी और पांड्याखेड़ी रेलवे ब्रिज के पास से नकली नोटो की डिलेवरी देने आये हिमांशु उर्फ चीनू पिता राजेश गौसर निवासी गऊघाट कालोनी और दिपेश पिता अनोखीलाल चौहान निवासी शिवगंगा सिटी हाटकेश्वर के पीछे को चिमनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके पास से 17.50 लाख के नकली नोट बरामद किये थे। पूछताछ में गिरोह से जुड़े सोनू टाटावत उज्जैन और सरगना राजेश बरबटे निवासी भोपाल के नामों का खुलासा हुआ था। पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाकर तलाश शुरू की थी। पिछले 7 माह से दोनों का सुराग तलाशने के प्रयास जारी थे। मंगलवार को चिमनगंज थाना पुलिस को खबर मिली कि नकली नोट गिरोह में शामिल सोनू टाटावत ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। एसआई सुरेन्द्र मंडलोई कोर्ट पहुंचे और आरोपी से पूछताछ के लिये 5 दिनों का रिमांड मांगा। न्यायालय ने मामला नकली भारतीय मुद्रा से जुड़ा होने पर आरोपी को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। एसआई मंडलोई ने बताया कि अब गिरोह के मुख्य सरगना राजेश की तलाश है, रिमांड पर लिये गये आरोपी से उसके संबंध में पूछताछ की जायेगी और पता लगाया जायेगा कि मामले का खुलासा होने से पहले नकली नोट कहां-कहां खपाये थे।

बारिश में धंसी सड़क, सीमेंट से भरा ट्राला नाले में पलटा

एमआर-5 रोड पर हादसा- सड़क की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने से व्यापारियों में नाराजगी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार सुबह एमआर-5 रोड पर सड़क धंसने से बड़ा हादसा हो गया। शिव शक्ति सीमेंट की दुकान पर माल उतारने पहुंचा सीमेंट से भरा ट्राला अचानक सड़क टूटने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने नाले में पलट गया।

हादसे में ट्राले में लदी करीब 3.50 लाख रुपए मूल्य की सीमेंट की बोरियां पानी में भीगकर पूरी तरह खराब हो गईं। राहत की बात यह रही कि ट्राला चालक सुरक्षित बच गया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब ट्राला दुकान के सामने माल उतारने के लिए सड़क किनारे खड़ा किया गया था। लगातार बारिश से नाले के पास सड़क के नीचे की मिट्टी बह चुकी थी, जिससे सड़क अंदर से खोखली और कमजोर हो गई थी। जैसे ही ट्राले का भार सड़क पर पड़ा, सड़क धंस गई और ट्राला संतुलन खोकर सीधे नाले में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

बार-बार शिकायत के बाद भी नहीं जागा निगम- स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों ने इस हादसे के लिए नगर निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि सड़क की जर्जर स्थिति और नाले के किनारे कटाव की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की गई थी, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई। लोगों का आरोप है कि यदि प्रशासन ने समय पर सड़क की मरम्मत कर दी होती तो लाखों रुपए के नुकसान के साथ यह हादसा टल सकता था।

व्यापारियों ने उठाए सवाल- व्यापारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में शहर की कई सड़कें खतरे का कारण बनी हुई हैं। कमजोर और धंसी हुई सड़कों से भारी वाहनों के साथ आम लोगों की जान भी जोखिम में है। उन्होंने निगम से तत्काल क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

शिप्रा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने जारी की चेतावनी- लगातार बारिश का असर मोक्षदायिनी शिप्रा नदी पर भी दिखाई दे रहा है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से घाटों और किनारे स्थित कुछ मंदिरों तक पानी पहुंच गया है। स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने नदी के गहरे और संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों तथा श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जलभराव वाले क्षेत्रों, नालों और नदी किनारों से दूर रहें तथा सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।

निर्मोही अखाड़े ने मौजूदा अखाड़ा परिषद को दिया समर्थन

उज्जैन में हुई बैठक में सर्वसम्मति से फैसला

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को लेकर चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को उज्जैन स्थित निर्मोही अखाड़े में बैठक आयोजित हुई। जिसमें पंच निर्मोही अखाड़े के पंचों ने सर्वसम्मति से मौजूदा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का समर्थन करते हुए घोषणा की कि आगामी नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज कुंभ मेले परिषद की अगुवाई में ही होंगे।

बैठक की अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज ने की। इस दौरान निर्मोही अखाड़े के महंत मदन मोहन दास महाराज, भगवान दास महाराज, सीताराम दास महाराज, महंत दिग्विजय दास महाराज सहित सभी पंचों ने परिषद के साथ रहने का निर्णय लिया। रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि निर्मोही अखाड़े के निमंत्रण पर शैव, निर्मल और उदासीन परंपरा के संत-महात्मा एकत्र हुए और सभी ने मिलकर आगामी कुंभ मेलों को एकजुट होकर आयोजित करने पर सहमति जताई। वहीं, श्रीमहंत मदन मोहन दास महाराज ने कहा कि देश की सर्वोच्च संत संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ निर्मोही अखाड़े के लाखों साधु-संत और नागा साधु जुड़े हुए हैं तथा वे कुंभ के शाही स्नान में भी परिषद के साथ शामिल होंगे।

बैठक में आनंद अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं परिषद के कोषाध्यक्ष महंत शंकरानंद सरस्वती महाराज, जूना अखाड़े के राष्ट्रीय सचिव महंत रामेश्वर गिरी महाराज, बड़ा उदासीन अखाड़े के प्रतिनिधि, निर्मल अखाड़े, अग्नि अखाड़े और आव्हान अखाड़े के संत-महात्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में संतों ने अखाड़ा परिषद को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और दुष्प्रचार पर भी चिंता जताई। परिषद के पदाधिकारियों का कहना था कि मौजूदा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पूर्ववत अपना कार्य करती रहेगी और आगामी कुंभ मेलों का संचालन भी इसी के नेतृत्व में होगा।

झपट्टा मारकर ट्रेन में सवार यात्रियों का छीन लेते थे मोबाइल

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। चलती ट्रेन के गेट पर खड़े यात्रियों का झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाले 2 बदमाशों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। दोनों नशे के आदी है और आउटर पर पटरियों के पास खड़े होकर गेट पर खड़े होकर मोबाइल पर बात करने वाले यात्रियों को निशाना बनाते थे। जीआरपी थाना प्रभारी अमित कुमार भावसार ने बताया कि 6 जुलाई को गुना के रहने वाले हेमंत जाटव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह इंटरसिटी एक्सप्रेस के जनरल कोच के गेट पर खड़ा होकर यात्रा कर रहा था। ट्रेन के उज्जैन स्टेशन से रवाना होने पर उसने परिवार को कॉल करने के लिये मोबाइल निकाला। उसी दौरान आउटर पर 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से वीवो कंपनी का मोबाइल छीन लिया। ट्रेन गति पकड़ चुकी थी और दोनों बदमाश पटरियों के बीच से दौड़ते हुये भाग निकले थे। शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 304 (2) का प्रकरण दर्ज किया गया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तलाश शुरू कर प्रधान आरक्षक श्याम सुंदर चौबे, दशरथ मेहरा, आरक्षक जनक भदौरिया, दिलीप लोधी और अनुप नारोलिया की टीम गठित की गई। 24 घंटे में झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाले दोनों आरोपी कान्हा मराठा और पुरूषोत्तम को जीरो पाइंट ब्रिज के पास आउटर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर वीवो कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया है। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पूर्व में चोरी और मारपीट के प्रकरण दर्ज होना सामने आया है। दोनों उज्जैन के रहने वाले है और नशा और दैनिक खर्चों के लिये वारदात को अंजाम देते है।

वर्षा ऋतु के दौरान विद्युत पोल और तारों का समय-समय पर उचित संधारण किया जाए

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। सांसद श्री अनिल फिरोजिया की अध्यक्षता में बुधवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में विगत बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान सांसद श्री फिरोजिया ने निर्देश दिए कि एम.आर. 05 सड़क क्षेत्र में ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास स्थित नाले से स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसका शीघ्र निराकरण किया जाए।

कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि आगामी सिंहस्थ 2028 के अंतर्गत 04 नवीन ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जूना सोमवारिया में स्थित जो भी ऊँचे चेंबर थे, उन्हें नीचे करवाया गया है।

सांसद श्री फिरोजिया ने निर्देश दिए कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए निगम/बोर्ड/प्राधिकरण की कॉलोनियों में ई.डब्ल्यू.एस. के जो भी मकान रिक्त हैं, वे शीघ्र-अतिशीघ्र पात्र हितग्राहियों को आवंटित किए जाएँ। नई कॉलोनियों के निर्माण के दौरान इनमें सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने जानकारी दी कि इस संबंध में स्थानीय कॉलोनाइजरों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

सिंहस्थ 2028 के अंतर्गत जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश सांसद द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भगवान श्री महाकालेश्वर की श्रावण और भादौ माह में निकलने वाली सवारी को ध्यान में रखते हुए सवारी मार्ग का दुरुस्तीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।बैठक में जानकारी दी गई कि ढाबा रोड पर निर्माण कार्य रात्रि में भी किए जा रहे हैं। आगामी 15 जुलाई तक उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सिंहस्थ 2028 और मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान सांसद श्री फिरोजिया ने निर्देश दिए कि गैस लाइन, पाइपलाइन और सीवरेज लाइन संबंधी कार्य में विशेष सावधानी बरती जाए। सिवरेज लाईन का कार्य पूर्ण सतर्कता के साथ किया जाए। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि नल-जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क निर्माण का कार्य तेज गति से किया जाए।

हिरासत में आया अस्पताल से भागा धोखाधड़ी का आरोपी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मकान का सौदाकर धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस जेल से प्रोटेक्शन रिमांड पर लेकर आई थी। बुधवार को मेडिकल कराने अस्पताल लेकर पहुंचे जहां से एक आरोपी भाग निकला था जिसे 3 घंटे की तलाश के बाद पुलिस ने फिर से हिरासत में लिया है।

चिमनगंज थाना क्षेत्र के तिरुपतिधाम कॉलोनी में रहने वाले राहुल मालवीय और उसकी मां जयश्री मालवीय द्वारा इंदिरानगर में रहने वाले नीरज पिता करुणा निधि श्रीवास्तव के खिलाफ मकान बेचने के नाम पर की गई लाखों की धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया था। तीनों को जेल भेजा जा चुका था। लेकिन तीनों के खिलाफ एक और मामला धोखाधड़ी का सामने आया उक्त मामले में भी पुलिस में प्रकरण दर्ज किया और तीनों को पूछताछ के लिए जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर थाने लेकर आई। बुधवार को तीनों को मेडिकल परीक्षण के लिए चरक अस्पताल लाया गया। जहां से पुलिस को चकमा देकर धोखाधड़ी का आरोपी नीरज श्रीवास्तव भाग निकला। आरोपी के भागने पर हड़कंप मच गया और उसकी सरगर्मी से तलाश शुरू की गई। 3 घंटे बाद खबर मिली कि अस्पताल से भागा आरोपी बहादुरगंज क्षेत्र की एक धर्मशाला में छुपा हुआ है। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी की और फरार आरोपी को हिरासत में ले लिया। दौरान आरोपी ने धर्मशाला से कूद कर भागने की कोशिश की लेकिन उसका पैर टूट गया। आरोपी के साथ धोखाधड़ी में शामिल मां और बेटे को गुरुवार दोपहर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

किनारे पर खड़ा सीमेंट से भरा ट्राला नाले में गिरा

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। बुधवार सुबह एमआर-5 मार्ग पर सड़क किनारे खड़ा सीमेंट से भरा ट्राला अचानक जमीन धसने पर नाले में जा गिरा। सीमेंट की बोरियां गीली होने पर लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है।

राजस्थान के रामगंज मंडी का रहने वाला अंकित पिता तुलसीराम 20 साल राजस्थान के मोडक स्थित सीमेंट फैक्ट्री से ट्राले में 840 सीमेंट की बोरियां भरकर बुधवार सुबह उज्जैन स्थित चिमनगंज थाना क्षेत्र के एमआर-5 मार्ग पर शिव शक्ति ट्रेडर्स पहुंचा था। उसने दुकान के सामने सड़क किनारे नाले के पास ताला खड़ा किया और। शिव शक्ति ट्रेडर्स के मलिक प्रेम मीणा को कॉल किया। प्रेम मीणा के आने पर चालक ने सीमेंट खाली करने की बात कही। जिस पर दुकान के समीप ही बने गोदाम तक ट्राला ले जाने की बात कही गई। चालक ट्राला स्टार्ट करता उससे पहले ही नाले के पास की जमीन अचानक धसने गई और ट्राला नाले में पलटी खा गया। बारिश के चलते नाले में पानी का बहाव तेज था सीमेंट की बोरियां गीली हो गई। जिसके चलते शिव शक्ति ट्रेडर्स के मालिक को 3-50 लख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। साला पलटने की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी क्रेन की मदद से ट्राले को नाले से बाहर निकाला गया है। प्रेम मीणा ने बताया कि कुछ दिन पहले ही इसी तरह टाइल्स से भरा ट्राला नाले में गिरा था। क्षेत्र में मार्ग निर्माण का कार्य चल रहा है ठेकेदार द्वारा नाले के किनारे ठीक से निर्माण नहीं किया गया है। नल की चौड़ाई भी 15 फीट से अधिक हो चुकी है आसपास भराव नहीं होने पर वाहन पलटने की घटना हो रही है।

मंदिर में चोरी करने वाला निकला बाइक चोर

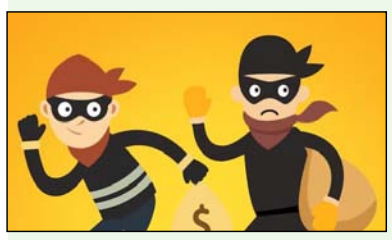

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मंदिर में हुई चोरी की वारदात में शामिल आरोपी को पुलिस में गिरफ्तार किया तो उसे चोरी की बाइक भी बरामद हो गई। पुलिस द्वारा मंदिर में हुई चोरी का सामान बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। तराना थाना प्रभारी रामनारायण सिंह भदोरिया ने बताया कि 2 दिन पहले समभाव पिता तकेसिंह पाटीदार, निवासी ग्राम इटावा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि श्री पूर्वमुखी हनुमान महादेव मंदिर में अज्ञात बदमाश में चोरी को अंजाम देकर पूजा-अर्चना में प्रयुक्त पीतल एवं तांबे के धार्मिक बर्तन, जलाधारी घड़ा, पूजा की थालियां एवं अन्य पूजन सामग्री, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 हजार थी। मंदिर में हुई चोरी को लेकर पुलिस ने बदमाश का पता लगाने के लिए टीम गठित की और बुधवार को भगवान पिता नारायण सिंह 35 वर्ष, निवासी ग्राम बरोठिया, थाना माकड़ोन, जिला उज्जैन को गिरफ्तार किया गया। चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर उसने मंदिर में वारदात करना स्वीकार कर लिया वहीं अन्य मामलों के संबंध में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा 5 जुलाई को गोपाल पिता नारायणसिंह यादव, निवासी ग्राम पाचारुण्डी, जिला आगर-मालवा की तराना से ही मोटरसाइकिल क्रमांक एम पी -42-एम एफ-1880 (बजाज डिस्कवर) चोरी करना कबूल किया गया। थाना प्रभारी के अनुसार उस मंदिर से चोरी हुई पूजन सामग्री बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

बारिश में खुले सीवरेज गड्ढों ने बढ़ाया खतरा

नगर निगम की लापरवाही पर नेता प्रतिपक्ष का हमला- विशेष मेंटेनेंस टीम बनाकर जिम्मेदारी तय करने की मांग

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। लगातार हो रही बारिश के बीच सीवरेज लाइन के लिए खोदे गए खुले गड्ढे और सड़कों पर फैली कीचड़ शहरवासियों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम और निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधूरे निर्माण और लापरवाही के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने हाल ही में सीवरेज लाइन में हुई एक व्यक्ति की मौत को भी इसी अव्यवस्था का नतीजा बताया और जिम्मेदार अधिकारियों व एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की।

नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि शहर की कई सड़कें खुदी पड़ी हैं और बड़े-बड़े गड्ढों के कारण लोगों का पैदल चलना और वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मार्ग अब भी बंद हैं, जबकि जिन रास्तों से आवाजाही हो रही है, वहां भी मुरम, गिट्टी और पेचवर्क नहीं कराया जा रहा है।

उन्होंने निर्माण कार्यों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि कई स्थानों पर मजदूर बिना हेलमेट, ग्लव्स और अन्य सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे हैं। श्रम नियमों की अनदेखी के कारण मजदूरों की जान जोखिम में पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि बारिश के चार महीनों के लिए नगर निगम विशेष मेंटेनेंस टीम गठित करे, जो सड़कों, गड्ढों और कीचड़ की तत्काल मरम्मत कराए। साथ ही निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की नियमित जांच कराई जाए और संबंधित एजेंसियों को गड्ढे भरने, मुरम-गिट्टी डालने तथा ठंडे डामर से पेचवर्क कराने के निर्देश दिए जाएं, ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके।

स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए वैल्यू एडेड कोर्स का चयन अनिवार्य

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वैल्यू एडेड कोर्स, संवैधानिक, मानवीय एवं नैतिक मूल्य तथा पर्यावरण शिक्षा एवं स्थिरता आधारित पाठ्यक्रमों का चयन अनिवार्य किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी करीकुलम एण्ड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम्स (सीसीएफपीजी), जून-2024 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के नवीन अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्नातकोत्तर विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में 2 क्रेडिट पॉइंट का एक वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम लेना होगा। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विषय समूहों अंतर्गत पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें रोजगार एवं उद्यमिता कौशल, योग एवं ध्यान द्वारा तनाव प्रबंधन, पर्यावरण मनोविज्ञान, शोध लेखन कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एथिक्स आदी।

दूसरी डेयरी के नाम के फर्जी बिल पर चल रहा था पनीर सप्लाई का कारोबार

खाद्य विभाग की दबिश में खुला मामला- पनीर जब्त कर जांच के लिए भेजा, पुलिस को भी दी जाएगी सूचना

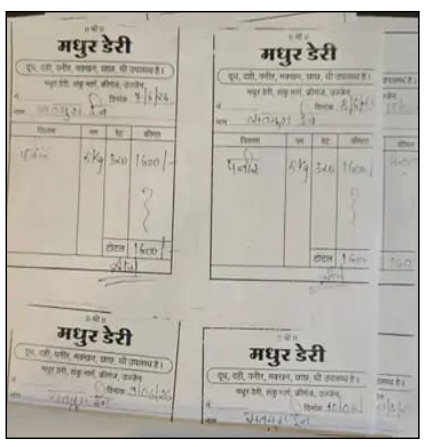

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में होटलों तक पहुंचने वाले पनीर की सप्लाई में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की कार्रवाई में खुलासा हुआ कि एक युवक एक डेयरी से पनीर खरीदकर दूसरी डेयरी के नाम के बिल के सहारे होटलों में सप्लाई कर रहा था। शिकायत मिलने पर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ा, पनीर जब्त कर उसके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। मामले में फर्जी बिलों के उपयोग की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस को भी सूचना दी जा रही है।

जानकारी के अनुसार महाकाल मंदिर क्षेत्र स्थित चौबीस खंभा माता मंदिर के पीछे संचालित सतयुग इन होटल में रोज की तरह पनीर की सप्लाई करने अतुल बढ़वार पहुंचा था। इसी दौरान पहले से मौजूद खाद्य विभाग की टीम ने उसे रोककर पूछताछ की। जांच में सामने आया कि वह नागझिरी स्थित यशोदा डेयरी से पनीर खरीदकर लाता था, लेकिन होटल संचालकों को फ्रीगंज स्थित मधुर डेयरी के नाम का बिल थमा देता था।

पूछताछ के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत शर्मा और बी.एस. देवलिया ने युवक से खाद्य लाइसेंस, पुराने बिल और अन्य दस्तावेज मांगे। प्रारंभिक जांच में बिलों में गड़बड़ी मिलने पर टीम ने मौके पर मौजूद पनीर जब्त कर लिया और उसके नमूने गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या दूसरे प्रतिष्ठान के नाम से बिल जारी कर पनीर की सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है। अब दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद यह भी स्पष्ट होगा कि सप्लाई किया गया पनीर गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है या नहीं।

उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जानकारी महाकाल थाना पुलिस को भी दी जाएगी। यदि जांच में फर्जी बिल, गलत दस्तावेज या खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद शहर के होटल और डेयरी कारोबार में हड़कंप मच गया है। विभाग का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में आगे भी लगातार जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।

चरक अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ प्रॉपर्टी घोटाले का आरोपी

दो आरक्षकों की मौजूदगी में इमरजेंसी गेट से भागा- प्रोडक्शन वारंट पर जेल से पूछताछ के लिए लाया गया था

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही बुधवार को उस समय सामने आई, जब प्रॉपर्टी धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद आरोपी नीरज श्रीवास्तव मेडिकल जांच के दौरान पुलिस को चकमा देकर चरक अस्पताल से फरार हो गया। आरोपी दो पुलिस आरक्षकों की निगरानी में अस्पताल लाया गया था, लेकिन वह इमरजेंसी गेट से भाग निकला। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई, जबकि पुलिस महकमे में भी हड़कंप की स्थिति बन गई।

जानकारी के अनुसार नीरज श्रीवास्तव, उसकी मां तथा एक अन्य आरोपी पर एक ही मकान को कई लोगों को बेचने, फर्जी रजिस्ट्री कराने और नकली दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में तीनों आरोपी केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बंद हैं। चिमनगंज मंडी पुलिस नीरज से पूछताछ के लिए उसे प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लेकर आई थी। पूछताछ की प्रक्रिया से पहले नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराने के लिए पुलिस आरोपी को चरक अस्पताल लेकर पहुंची। इसी दौरान मौका मिलते ही नीरज पुलिसकर्मियों को चकमा देकर इमरजेंसी गेट से बाहर निकल गया। बताया जा रहा है कि वह सीएमएचओ कार्यालय की ओर से होते हुए अस्पताल के पीछे के रास्ते से क्षीरसागर रोड की तरफ भाग निकला।

आरोपी के फरार होने की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तत्काल अस्पताल और आसपास के क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। कई स्थानों पर नाकाबंदी भी की गई, लेकिन देर शाम तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लग सका। घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दो आरक्षकों की निगरानी में मौजूद आरोपी का इस तरह फरार हो जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा रहा है।चिमनगंज मंडी थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने बताया कि आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाया गया था। मेडिकल जांच के दौरान उसके भागने की सूचना मिलते ही पुलिस की अलग-अलग टीमें उसकी तलाश में लगा दी गई हैं। उन्होंने दावा किया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।